छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 199 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 01 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

बस्तर के कायाकल्प का रोडमैप लेकर पीएम मोदी से मिले सीएम साय

यूरिया प्लांट, विद्युत ग्रिड और एआईआईए की स्थापना के लिए मांगा केंद्र का सहयोग

छ.ग.फ्रंटलाइन नईदिल्ली/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की समन्वित रणनीति के परिणामस्वरूप बस्तर आज व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, हवाई संपर्क, आजीविका, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस परिवर्तन को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10.42 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं, अब 14 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।

यूरिया परियोजना के लिए मंजूरी देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा सहायक आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के ऐसे 461 गांवों का विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा, जहां पूर्व में सुरक्षा एवं भौगोलिक कारणों से विद्युत ग्रिड पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था और वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्युत आपूर्ति से इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आजीविका और लघु उद्यमों के विस्तार को गति मिलेगी तथा दूरस्थ अंचलों में विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

रायपुर या बस्तर में एआईआईए की स्थापना का आग्रह

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए)की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध विरासत है। राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं विकसित होंगी।

योजनाओं से 5,542 गांवों के 39 लाख लाभांवित

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष 'बस्तर विजन' की विस्तृत जानकारी रखते हुए बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्त मुन्ने' के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में शासन की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, वनाधिकार, प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ और पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील रहे गांवों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने से शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

ओरछा-जगरगुंडा में बनेगा एजुकेशन सिटी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को पुन: प्रारंभ किया गया है। जिन गांवों में कभी बच्चों के लिए नियमित शिक्षा तक पहुंच बड़ी चुनौती थी, वहां अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि

दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय सुविधाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और आवश्यकता के अनुरूप उन्हें चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा गया है। बस्तर में चिकित्सा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ गीदम में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के स्थायी विकास के लिए सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। लगभग 3,513 करोड़ की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है। इस रेल संपर्क से बस्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। जगदलपुर से नियमित हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। उन्होंने रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण की प्रगति तथा इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने कहा कि बैराज परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।

वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री ने बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे विश्वस्तरीय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और प्रमुखता से स्थापित करने के लिए अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर का विकास उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के संरक्षण के साथ किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित हों। बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने बदलाव का संदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में तेजी से बदल रहे औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें अनेक परियोजनाओं पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, गारमेंट, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा इंट्राऑक्यूलर लेंस निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता आने के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर निर्मित होंगे।

छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान, निवेश अनुकूल वातावरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद व्यवस्था विकसित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नियामकीय सुगमता और संस्थागत वातावरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026' की जानकारी दी। इससे निवेशकों को निश्चितता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 500 करोड़ के राज्य एआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ का मजबूत प्रदर्शन

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति और राजस्व वृद्धि से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करते हुए राजकोषीय एवं राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। राज्य में जीएसटी राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं खनिज राजस्व में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खनिज क्षेत्र में नई संभावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के पहले टिन ब्लॉक और लिथियम ब्लॉक की नीलामी कर छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

नागरिक-केंद्रित सुशासन को मिली नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में निरंतर सुधार कर रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था भी विकसित की गई है। राजस्व प्रशासन में व्यापक डिजिटल सुधार करते हुए रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामांतरण की व्यवस्था लागू की गई है। आधार और वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा ने पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया है।

सीईओ की लापरवाही से बेगुनाह सरपंच के जेल जाने की नौबत बनी

एसडीएम न्यायालय ने किया गिरफ्तारी वारंट जारी, खेत से उठाकर ले गई पुलिस

कांग्रेस के सख्त तेवर के बाद सीईओ ने बदला सरपंच का नाम, सरपंच ने कहा- मेरे को जेल भेजो

सरपंच रामसाय मिंज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जनपद पंचायत अंबिकापुर की घोर लापरवाही और गलत रिकार्ड संधारण के कारण सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष और ग्राम सरईटिकरा के सरपंच रामसाय मिंज को बेगुनाह होते हुए भी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार करके एसडीएम कोर्ट में पेश किया। मामला ग्राम चीताबहार में 2020-21 में हुए 1 लाख 75 हजार 93 के सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के नाम पर हुए गबन से जुड़ा है।

एसडीएम न्यायालय अंबिकापुर द्वारा 06.04.2026 को जारी 'कारण बताओ नोटिस' क्रमांक 1047 में ग्राम चीताबहार के तत्कालीन सरपंच रामसाय और तत्कालीन सचिव देवेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि चीताबहार में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए आहरित 1,75,093 की राशि जमा नहीं की गई है। इसके बाद 20.07.2026 को एसडीएम कार्यालय से रामसाय मिंज और देवेन्द्र कुमार के नाम से अलग-अलग गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए। वारंट में लिखा है कि दोनों ने 87,546-87,546 रुपये का गबन किया है और उन्हें 24.07.2026 को पेश किया जाए।

जमानत लेने से किया इन्कार

इसी वारंट के आधार पर दरिमा थाना पुलिस ने अलसुबह रामसाय मिंज को उनके खेत से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न ब्रश करने दिया गया न कपड़े बदलने दिए गए। थाने में प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें दोपहर करीब 12.30 बजे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। यहां मौजूद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने रामसाय मिंज के समक्ष दस्तावेज को देखा, तो पता चला कि वे घटना के समय चीताबहार के सरपंच ही नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया और जेल भेजने की मांग की।

जनपद सीईओ ने खुद गलती स्वीकारा-हंगामे के बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने 31.07.2026 को एसडीएम को पत्र क्रमांक 3122 भेजकर गलती स्वीकार की। पत्र में सीईओ की ओर से उल्लेख है कि 'सूचित बैठक में सरपंच/सचिव ग्रुप में आरआरसी वसूली सूची में मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाता रहा, जिसमें सरपंच से वसूली हेतु रामसाय का नाम अंकित था, किन्तु इस संबंध में रामसाय सरपंच द्वारा कोई भी जानकारी कार्यालय में नहीं दी गई। फलस्वरूप सरपंच सरईटिकरा के रूप में रामसाय का नाम अंकित रहा।' पत्र में आगे लिखा है कि 'आज स्वयं सरपंच रामसाय ने जानकारी दी एवं सचिव सरईटिकरा से 31.07.2026 को जानकारी प्राप्त हुई कि वर्ष 2020-25 में शिवनाथ राम भगत सरपंच के पद पर कार्यरत थे। रामसाय वर्तमान में ग्राम पंचायत सरईटिकरा के सरपंच पद पर कार्यरत नहीं हैं। अंत में उल्लेख है कि 'अत: ग्राम पंचायत चीताबहार सरपंच वर्ष 2020-25 रामसाय के स्थान पर शिवनाथ राम भगत पूर्व सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।"

कांग्रेस का आरोप: साजिश-घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम कार्यालय कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विनय शर्मा, दरिमा ब्लॉक अध्यक्ष नारद गु प्ता, जनपद अध्यक्ष विक्रम सोनपाकर, उपाध्यक्ष सतीश यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। इन्होंने कहा जिला पंचायत की निरंकुश कार्यप्रणाली का प्रभाव जनपद पर पड़ने लगा है। इधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने सीईओ जनपद से फोन पर बात करके गलती सुधारने को कहा। राकेश गुप्ता ने कहा 'यह त्रुटि नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि को अपमानित करने की साजिश है। सीईओ के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रतिष्ठा पर आई आंच का कौन जवाबदेह-जनपद पंचायत का 06.08.2024 का पत्र क्रमांक 1480 जिसमें वसूली योग्य 1,75,093 में से 87,546 रामसाय/सरपंच के नाम और 87,547 रुपये देवेन्द्र कुमार/सचिव के नाम दर्ज है। कार्यकाल 05/2021 लिखा है। 31.07.2026 के पत्र में सीईओ ने माना कि 2020-25 में चीताबहार के सरपंच शिवनाथ राम भगत थे, रामसाय नहीं। सवाल यह उठता है कि जिस सीईओ को ये नहीं पता कि किस गांव का सरपंच कौन है, वो सरगुजा के 100 से ज्यादा पंचायतों कैसे चलाएगा? गलत रिकार्ड के आधार पर बेगुनाह को गिरफ्तार करके लाने का जिम्मेदार कौन होगा है? वो भी ऐसी स्थिति में जब गिरफ्तार करके लाया सरपंच जनपद क्षेत्र के सरपंचों का अध्यक्ष हो। ऐसे में मान प्रतिष्ठा पर आई आंच की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

ऑपरेशन क्लीन: 24 घंटे में सप्लायर-विक्रेता गिरफ्तार, 100 नशीले इंजेक्शन जब्त

बलरामपुर से आ रहा था माल, सहायक आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में दबिश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई है। 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत टीम ने 24 घंटे के अंदर एक विक्रेता और एक सप्लायर को गिरफ्तार करके इनके पास से 100 नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में की गई।

जानकारी के मुताबिक, 30 जुलाई को सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि बलरामपुर जिला के कुसमी का अविनाश पैकरा, शांतिपारा अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर नशीले इंजेक्शन बेच रहा है। मुखबिर ने बताया कि वह अभी अपने कमरे पर ही मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल दबिश दी। दबिश के दौरान एक युवक बैग लेकर पीछे से भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अविनाश पैकरा बताया। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 15 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 15 नग एविल इंजेक्शन मिला। इस पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि वह नशीले इंजेक्शन अनपारा थाना रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर निवासी अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू से खरीदकर लाता है।

बलरामपुर के जंगल से सप्लायर बिट्टू गिरफ्तार

अविनाश पैकरा की निशानदेही पर टीम ने 31 जुलाई को जिला बलरामपुर में दबिश दी। टीम ने विमलापुर के जंगल से अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से 50 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 50 नग एविल इंजेक्शन मिला, जिसे टीम ने बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

90 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन विक्रेता जेल दाखिल

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत यह एक बड़ी सफलता है। अंबिकापुर के 90 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन विक्रेता जेल जा चुके हैं। अब कुछ लोग जिला बलरामपुर और सूरजपुर से माल लाकर यहां बेच रहे हैं। उन पर हमारी कड़ी नजर है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।'

कार्रवाई में ये रहे शामिल-कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक टीआर केहरी, सहायक उपनिरीक्षक रमेश दुबे, प्रधान आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पाण्डेय, रणविजय सिंह, रोहित सोनवानी एवं महिला सैनिक राजकुमारी सिंह और चंद्रावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

व्यापारियों ने किया चक्काजाम, 5 घंटे ठप रहा आवागमन

एक करोड़ के जेवरात की चोरी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होने से आक्रोश

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। एक करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवरात की दिन-दहाड़े उठाईगिरी की घटना के आरोपी का पता आज पर्यंत नहीं चल पाया है। ऐसे में व्यापारियों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फूट पड़ा। व्यापारियों ने घटना के विरोध में नगर बंद का आह्वान किया। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 5 घंटे शहर की सभी दुकानें बंद रहीं और मुख्य मार्ग कारगिल चौक पर चक्काजाम करके जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारी संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठन और नगरवासी शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार करने तथा चोरी गए जेवरात की बरामदगी की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि दिन-दहाड़े इतनी बड़ी वारदात ने पूरे नगर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्होंने कहा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद से एक करोड़ के जेवरात को लेकर गायब हुआ आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।

एएसपी ने मांगा एक सप्ताह का समय-चक्काजाम की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी प्रतिनिधियों से घंटों चर्चा की। एएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले को गंभीरता से ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। उन्होंने खुलासे के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इनके आश्वासन के बाद व्यापारियों ने चक्काजाम समाप्त किया।

उग्र आंदोलन करने की चेतावनी-व्यापारी संघ ने साफ चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा नहीं हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने नगर में व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मार्ग में दोनों ओर लगी लंबी कतार-चक्काजाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार की वाहनों का आना-जाना पूर्णत: बाधित रहा। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे।

कैलाशपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में ताला तोड़कर 3.56 लाख से अधिक का सामान व नगद चोरी

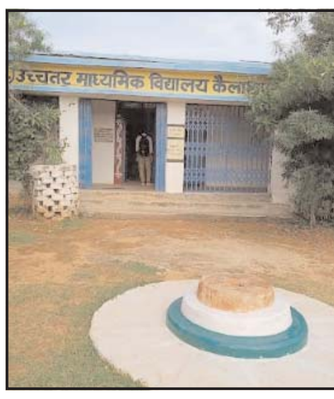

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाशपुर में शुक्रवार सुबह एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। अज्ञात चोरों ने स्कूल के मुख्य शटर और कई कमरों के ताले तोड़कर करीब 3 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ-साथ विद्यार्थियों की फीस के लगभग 56300 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रबंधन ने जयनगर थाना में लिखित शिकायत दी है। प्राचार्य डॉ. अमृता सिंह द्वारा थाना में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार शुक्रवार सुबह वह अपने सहयोगी शिक्षकों यूगल निकुंज, रविसन पटेल, प्रणव चंद्र मंडल सहित अन्य स्टाफ के साथ विद्यालय आ रही थीं। इसी दौरान करीब सुबह 9.35 बजे भृत्य विजय राजवाड़े ने फोन कर बताया कि स्कूल के बाहर लगे तीनों शटरों के ताले टूटे हुए हैं और अज्ञात व्यक्ति ने विद्यालय में चोरी कर ली है। सूचना मिलते ही प्राचार्य तत्काल विद्यालय पहुंच देखा कि मुख्य शटर के सभी ताले टूटे हुए थे। इसके बाद जब कार्यालय और कक्षों की जांच की गई तो चोरी की पूरी घटना सामने आई। प्राचार्या ने बताया कि चोरों ने कार्यालय कक्ष का ताला तोड़कर वहां रखे कंप्यूटर सेट, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन चोरी कर ली है। इतना ही नहीं कार्यालय में रखी दो अलमारियों के ताले भी तोड़ दिए गए, जिससे अंदेशा है कि चोरों ने वहां रखे अन्य दस्तावेजों और सामान की भी तलाश की है। चोरों ने विद्यालय की 12 वीं आर्ट्स कक्षा का ताला तोड़कर वहां लगे प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, बैटरी और इमेजिंग सिस्टम चोरी कर लिए हैं। इसके बाद बगल में स्थित स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर वहां से भी प्रोजेक्टर और इमेजिंग सिस्टम उठा ले गए हैं। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार चोरी हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। चोरों ने बरामदे में स्थित शिक्षक बैठक स्थल की टेबल का लॉकर तोड़कर उसमें रखी विद्यार्थियों की फीस की करीब 56300 रुपए नकद राशि भी चोरी कर ली है।

सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा डॉग स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंच विवेचना शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि सप्ताह भर पूर्व ही अज्ञात चोरों द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल अजबनगर को भी अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

फिल्टर प्लांट की निविदा में नई शर्त जोड़ी, केंद्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के सिविल विभाग द्वारा जारी फिल्टर प्लांट एवं इंटेक वेल के दो वर्षीय रखरखाव और मरम्मत कार्य की निविदा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निविदा में शामिल कुछ शर्तों को अनावश्यक और प्रतिस्पर्धा सीमित करने वाला बताते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। क्षेत्र के ठेकेदारों शितिकांत स्वाई, सज्जन कुमार अग्रवाल, तपन कुमार विश्वास, सरगुजा ब्रिक्स के हस्ताक्षरयुक्त शिकायत में कहा गया है कि रखरखाव एवं मरम्मत कार्य फिल्टर प्लांट एवं इंटेक वेल, बिश्रामपुर टाउनशिप की निविदा की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित है। आरोप है कि निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए फिल्टर प्लांट संचालन का पूर्व अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि एसईसीएल के अन्य क्षेत्रों में समान प्रकृति की निविदाओं में ऐसी शर्त नहीं रखी जाती।शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा सीमित होने के साथ कुछ विशेष ठेकेदारों को लाभ मिलने की आशंका पैदा होती है।

शिकायत में यह भी आपत्ति जताई गई है कि निविदा में फिल्टर प्लांट में उपयोग होने वाले मैकेनिकल पार्ट्स की व्यवस्था और आपूर्ति का दायित्व भी ठेकेदार पर डाला गया है, जबकि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ऐसे पार्ट्स की खरीद और आपूर्ति एसईसीएल के मैटेरियल मैनेजमेंट विभाग द्वारा की जाती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह कार्य मुख्य रूप से लेबर सप्लाई एवं संचालन व रखरखाव से संबंधित है। ऐसे में अतिरिक्त और असामान्य शर्तें जोड़ने से पात्र ठेकेदारों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है तथा निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से मांग की गई है कि दोनों बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि शिकायत सही पाई जाए तो निविदा में जोड़ी गई अनावश्यक शर्तों को हटाकर आवश्यक संशोधन कराया जाए, ताकि सभी पात्र ठेकेदारों को समान अवसर मिल सके तथा निविदा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

निरीक्षण पाई गई गंभीर लापरवाही, बड़कागांव समिति प्रबंधक निलंबित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर के निरीक्षण में रासायनिक खाद के ऑनलाइन स्टॉक एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाए जाने पर समिति प्रबंधक श्री भागवत प्रसाद गुप्ता

को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के द्वारा 28 जुलाई 2026 को बड़कागांव सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ऑनलाइन स्टॉक एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अंतर पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जून माह में समिति में 560 बोरी यूरिया की आवक हुई थी, लेकिन स्टॉक पंजी में जिसका इंद्राज नहीं किया गया। बड़कागांव समिति में भौतिक सत्यापन के दौरान किसानों द्वारा बताया गया कि बार-बार समिति का चक्कर लगाने पश्चात भी उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

रासायनिक खाद वितरण, स्टॉक रखरखाव एवं संधारण में लापरवाही के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़कागांव प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा तत्कालीन समिति प्रबंधक श्री भागवत प्रसाद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

श्रमिक नेता सुरेन्द्र पांडेय सहित सत्रह कर्मी हुए सेवानिवृत्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक नेता सुरेन्द्र कुमार पांडेय सहित सत्रह कामगार 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सभी सेवानिवृत हुए कर्मियों के सम्मान में यूनिट स्तर पर विदाई समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। बिश्रामपुर क्षेत्र में कार्यरत 17 कर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें सुरेन्द्र कुमार पांडेय के अतिरिक्त नगीना प्रसाद, रघुनंदन, बुधराम, अजर साय, प्रदीप सिंह, शांतनु मुखर्जी, सुरेन्द्र प्रसाद, हुकुम साय, प्रशांत कुमार दुबे, बाली राम, संजीव कुमार सिंह, राजू सिंह, जगदीश प्रसाद यादव, मनोज कुमार मिश्रा, बलबीर सिंह, शिवा शामिल हैं।

पंप हाउस से मोटर पंप चोरी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। करंजी पुलिस ने नवापारा निवासी एक ग्रामीण के पंप हाउस से पंप चोरी करने के मामले में गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है।

करंजी पुलिस ने बताया कि ग्राम नवापारा निवासी श्यामलाल राजवाड़े के पंप हाउस का ताला तोड़कर पंप चोरी कर ले जा रहे गांव के ही आरोपी राजेश पिता साधारण प्रजापति व कृष्णा पिता साधुराम प्रजापति को पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से चोरी किए गए मोटर पंप को जब्त कर उन्हें न्यायालय पेश कर दिया है।

बतरा डेम हादसा में तीन मछुआरों की मौत पर ठेकेदार के खिलाफ जुर्म दर्ज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। करंजी पुलिस चौकी क्षेत्र के बतरा डेम में गत दिनों 22 जून को नाव पलटने से तीन मछुआरों की मौत के मामले में पुलिस ने करीब सवा माह की जांच के बाद मछली ठेकेदार 36 वर्षीय विनोद केवट निवासी हर्रापारा भैयाथान के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत जुर्म दर्ज किया है। करंजी पुलिस ने बताया कि घटना के दिन समिति द्वारा बारिश के मौसम में मछली पकड़ने से मना किए जाने के बावजूद ठेकेदार नौ कर्मियों के साथ देर रात दो नावों और जाल लेकर डेम में

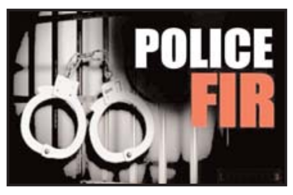

मछली पकड़ने पहुंचा था। रात करीब 1.30 बजे एक नाव अनियंत्रित हो गई। चार लोग दूसरी नाव में चढ़ गए, जबकि समयलाल, जगलाल और कंवल साय डेम के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि नई आशाएं आदिवासी सहकारी मछुआ समिति ने घटना से दो दिन पहले ही ठेकेदार को बारिश में मत्स्याखेट प्रतिबंधित होने की जानकारी देकर नाव और जाल हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके वह अंतिम बार मछली पकड़ने की बात कहकर डेम पहुंचा था। साथी मछुआरों के बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।

डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया प्रेमचंद जयंती

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। डीएवी पब्लिक स्कूल बिश्रामपुर में प्राचार्य श्रीमती अनामिका भारती के मार्गदर्शन में 31 जुलाई को महान हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कक्षा नवमीं एवं दसवीं के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं व्याकरण तथा प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता की टीमों को मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के आधार पर रंगभूमि और कर्मभूमि नामकरण दिया गया। रंगभूमि टीम में अनन्या यादव, राखी पटेल, पलक रौटेला, महवीज फातिमा, आयुष कुमार एवं समवर्ती सिंह और कर्मभूमि टीम में ऋषिता कुर्रे, दिव्या सिन्हा,आराध्या तिवारी, श्रेया सिंह, अंशकुमार उपाध्याय व अयांश कुशवाहा प्रतिभागी रहे। प्रश्नमंच प्रतियोगिता का सफल संचालन हिंदी शिक्षक एएम चौबे ने किया।प्राचार्य अनामिका भारती ने अपने उद्बोधन में प्रेमचंद जी के साहित्य और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी आज के डिजिटल युग में भी उनका साहित्य अद्यतन प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं हमें संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। यदि हम नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और उनमें निहित मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने प्रश्नमंच प्रतियोगिता में सम्मिलित सभी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन कर प्रतियोगिता के विजयी टीम की घोषणा की। प्रतियोगिता में कर्मभूमि टीम 165 अंकों के साथ विजेता बनी और रंगभूमि टीम 155 अंकों के साथ उप विजेता रही। हिंदी शिक्षिका शोभा नामदेव ने कहा कि आज हम ऐसे महान साहित्यकार की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने लेखन से समाज को नई दिशा दी। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सत्य, ईमानदारी, समानता, करुणा और मानवता का संदेश दिया। कक्षा 12 वीं की छात्रा एरीना रुखसार ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर निरंतर संघर्ष करते रहने, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे।मंच संचालन शोभा नामदेव ने किया। आयोजन को सफल बनाने में हिंदी विभाग के शिक्षक एएम चौबे, एलआर साहू, रूबी कुर्रे, राजकुमारी जायसवाल एवं ओंकार प्रसाद साहू, क्रीड़ा शिक्षक पीके वैद्य, सांस्कृतिक प्रभारी बिमान घोष सक्रिय रहे।

नपं बिश्रामपुर के सीएमओ सुशील कुमार की सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत बिश्रामपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार तिवारी के 30 जुलाई को सेवानिवृत्ति उपरांत सम्मान समारोह कर विदाई दी गई।सेवानिवृत्त सीएमओ तिवारी 42 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति सीएमओ तिवारी को श्रीफल, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नपं अध्यक्ष निर्मला यादव, उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, पार्षद लक्ष्मीबाई यादव, अर्चना लकड़ा, राहुल खातरकर, विनोद सरवटे, रविंद्र विश्वकर्मा, अमरेश प्रसाद, संजीत यादव, रविशंकर बऊवा, नीलम मिश्रा, रामजीत यादव, शकुंतला सोनी, पूर्व नपं अध्यक्ष राजेश यादव, एल्डरमैन सतीश तिवारी, नंदलाल राजवाड़े, शिक्षक गौरीशंकर पांडेय, पोरेश सिन्हा, उप अभियंता अख्तर आलम, सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद यादव, रनदीप दास, समूह की अध्यक्ष भारती गुप्ति, शशि शर्मा, आकाश सिन्हा, परवेज खान, अब्दुल हैदर, अरविंद सोनी, स्वच्छता दीदीयां एवं सफाई मित्र उपस्थित थे। मंच का संचालन राजकिशोर चौधरी ने किया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई

मालवाहक पिकअप में सवारी ढोने पर 3 हजार रुपये का जुर्माना

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात एवं परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

इसी कड़ी में वाड्रफनगर में जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने एक मालवाहक पिकअप वाहन को रोककर जांच की। इस दौरान पाया गया कि वाहन का उपयोग नियमों के विपरीत सवारियों के परिवहन के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित पिकअप वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही वाहन चालक को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। इस दौरान वाहन चालक को जानकारी दी गई कि मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करना मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन होने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में जांच अभियान निरंतर जारी रहेगी। विशेष रूप से मालवाहक वाहनों में सवारियों के परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें।

आचरण नियमों के उल्लंघन पर सहायक शिक्षक निलंबित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला सहायक) श्री शिवा यादव को गंभीर शिकायतों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी की संयुक्त जांच समिति ने शिकायतों की जांच की। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हुआ कि श्री यादव के विरुद्ध पूर्व में भी गुड टच-बैड टच संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्हें कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि उनके द्वारा विद्यालय परिसर में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से कई शिक्षिकाएं असहज महसूस करती थीं। इसके अलावा सहकर्मियों के प्रति अभद्र व्यवहार एवं अन्य शिकायतों की भी उपलब्ध अभिलेखों और पूर्व शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। संयुक्त जांच समिति ने इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा निलंबन की अनुशंसा की थी।

अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

सिपेट कोरबा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। केन्द्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), कोरबा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न दीर्घकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इन पाठ्यक्रमों में मुख्य रूप से डीपीएमटी (डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी) और डीपीटी (डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी) शामिल हैं, जो एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सूरजपुर जिले के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद या अन्य उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रायोजित करने का प्रावधान किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

इच्छुक छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत कर भारत सरकार द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान में तकनीकी कौशल प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। कोर्स पूर्ण करने के पश्चात छात्रों को ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल डिवाइस निर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान किये जायेंगे। आवेदन फॉर्म जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. सूरजपुर के बगल में, पतरापारा, ग्राम पंचायत पर्री, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में कार्यालयीन समय के दौरान जमा किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर को मिली सड़क विकास की बड़ी सौगात

चार ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 8.44 करोड़ रुपये से अधिक की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

आवागमन होगा सुगम, स्थानीय लोगों में खुशी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल जिले के चार महत्वपूर्ण ग्रामीण पहुंच मार्गों के निर्माण कार्यों के लिए कुल 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़क निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। शासन की इस स्वीकृति से स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार बुलडेगा से रेचवाघाट पहुंच मार्ग के 1.20 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा दैनिक आवागमन में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। इसी प्रकार खुंटापानी से सलियामुड़ा पहुंच मार्ग के 3 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 46 लाख 67 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मार्ग क्षेत्र के कई ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क निर्माण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और कृषि उपज के परिवहन में भी सुविधा मिलेगी। वहीं कोसमभावना से बनगांव पहुंच मार्ग के 1.20 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य, जिसमें पुल-पुलिया का निर्माण भी शामिल है। इसके लिए 1 करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। पुल-पुलिया निर्माण होने से बरसात के दौरान आवागमन बाधित होने की समस्या दूर होगी और ग्रामीणों को पूरे वर्ष सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा।इसके अलावा बुलडेगा मेन रोड से सुकबासुपारा होते हुए भिंजपुर पहुंच मार्ग के 2.50 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के अनेक गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इन सभी सड़क निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद संबंधित क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ-साथ किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। विद्यार्थियों, मरीजों एवं आम नागरिकों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का जीवन और अधिक सुगम बनेगा।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/ समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/ समग्र शिक्षक फेडरेशन ने कलेक्टर रेना जमील से मुलाकात कर रामानुजनगर विकासखण्ड में संकुल समन्वयकों को हटाने की गई एक पक्षीय कार्रवाई को निरस्त करते हुए उन्हें पुनः बहाल किए जाने की मांग की है। फेडरेशन के पदाधिकारीयों ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि रामानुजनगर विकासखण्ड के कुछ संकुल समन्वयकों को नियम विरुद्ध संलग्नीकरण बताकर एकतरफा उनके पदस्थ संस्था हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। जबकि उनमे से क ई समन्वयकों का काम बेहद सराहनीय रहा है ।वे स्कूलों में शासन के मंशानुरूप अध्यापन कार्य के साथ संकुल के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। फेडरेशन ने जिला समन्वयक द्वारा की गई इस कार्रवाई को विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा है कि जिले में कहीं भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसे नियम के विपरीत मानते हुए जिले में बनी व्यवस्था से अपने निजी हितों के लिए छेड़छाड़ किया जाना बताते हुए इस आदेश को तत्काल निरस्त कर सभी समन्वयकों को यथावत रखे जाने की मांग कलेक्टर से की है। कलेक्टर से मुलाकात करने वालों में फेडरेशन के जिलाध्यक्ष विजय साहू , शशिभूषण दुबे,नवल किशोर गुप्ता, प्रवीण श्रीवास्तव,अमोल सिंह,बोश प्रताप सिंह, बनारसी सिंह, राजेश सिंह आदि शामिल थे। सेटिंग की चर्चा जोरों पर-- विकासखण्ड अंतर्गत 35 संकुल केंद्र हैं जिनमें से छः संकुल समन्वयकों ने अधिकारियों के कथित दबाव के कारण स्वयं इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पांच संकुल समन्वयकों को नियम विरुद्ध संलग्नीकरण बताकर योजनाबद्ध तरीके से हटा दिए जाने के बाद 11 संकुल समन्वयकों का पद रिक्त है। उन्हें भरे जाने की सुगबुगाहट के बीच यह चर्चा है कि समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके लिए सेटिंग करने में लगे हुए हैं। कही पर लेन-देन की सेटिंग चल रही है तो 11 में से कम से कम चार संकुलों में जिला समन्वयक अपनों को उपकृत करने के प्रयास में लगे हुए हैं ।इन पदों को कब भरा जाएगा, क्या नियम प्रकिया के तहत नियुक्तियां हो पाएंगी इस पर सवाल व अटकलबाजियां तेज हो गई हैं।

विधायक ने स्वेचछानुदान राशि का चेक हितग्राहियों को किया वितरित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने 20 लाख रुपए स्वेच्छानुदान का हितग्राहियों को चेक वितरित किया। शुक्रवार को विधायक भूलन सिंह के निवास कार्यालय पटना में आयोजित कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्वेचछानुदान राशि का चेक हितग्राहियों को वितरित किया गया। जनपद पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, मंत्रीयों द्वारा इलाज, शिक्षा व अन्य जरूरतमंदों को दिए गए सहायता राशि 163 हितग्राहियों को 20 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह, उपाध्यक्ष रामप्रताप साहू, विधायक प्रतिनिधि संत साहू भाजपा मंडल महामंत्री सौभाग्य दुबे,दौलत प्रताप सिंह,खेलसाय राजवाड़े सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सहायता राशि का चेक पाकर हितग्राहियों ने विधायक भूलन सिंह का आभार जताया।

कलेक्टर रोहित व्यास ने सन्ना क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा

जश लर्न के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर, शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर- कलेक्टर रोहित व्यास ने तहसील कार्यालय सन्ना में सन्ना क्षेत्र के विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जश लर्न कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों एवं शैक्षिक संकुल समन्वयकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने पाठ्यपुस्तकों के शत-प्रतिशत वितरण, विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण, शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, स्मार्ट क्लास संचालन तथा जश लर्न कार्यक्रम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने जश लर्न कार्यक्रम के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिले में कक्षा तीसरी से पांचवी तक के विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संक्रियाओं में दक्ष बनाने के उद्देश्य से संचालित इस कार्यक्रम से बच्चों में गणित के प्रति रुचि, आत्मविश्वास एवं आधारभूत गणितीय समझ विकसित होगी, जिससे वे भविष्य की उच्च कक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। कलेक्टर ने जश लर्न कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन करने वाले शिक्षकों की सराहना की तथा जिन विद्यालयों में कार्यक्रम अपेक्षित स्तर पर संचालित नहीं हो रहा है, वहां आवश्यक सुधार करते हुए परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी

एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री व्यास ने सभी विद्यालयों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने, पाठ्यपुस्तकों का वितरण तत्काल पूर्ण करने तथा नवप्रवेशी विद्यार्थियों की अपार आईडी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की नियमित एवं शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। अनुपस्थित विद्यार्थियों के पालकों से नियमित संपर्क स्थापित कर अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी लेने तथा उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र समय पर बनवाने के लिए आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का नियमित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोचक एवं प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। बैठक में बगीचा एसडीएम श्री समीर बड़ा, प्रभारी तहसीलदार श्री तोष कुमार सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री सुदर्शन पटेल, संकुल प्राचार्य, शैक्षिक संकुल समन्वयक तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर व्यास ने सन्ना तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण

कलेक्टर रोहित व्यास ने सन्ना तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त शासकीय फाइलों का संचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों का नियमानुसार ई-कोर्ट प्रणाली के माध्यम से संचालन एवं प्रेषण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण तथा आरबीसी खंड 6-4 से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर रोहित व्यास ने केसरा एवं सन्ना में महाविद्यालय भवन निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के अनुसार और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर - कलेक्टर रोहित व्यास ने गुरुवार को जनपद पंचायत मनोरा के ग्राम केसरा में प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय भवन हेतु चिन्हांकित भूमि तथा सन्ना में निमार्णाधीन महाविद्यालय भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों भवनों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा, उच्च गुणवत्ता तथा सभी तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन करते हुए कराया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि महाविद्यालय भवनों का निर्माण विद्यार्थियों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करें। उन्होंने भवन निर्माण के साथ-साथ विद्युत, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा महाविद्यालय तक विद्यार्थियों के सुगम आवागमन के लिए गुणवत्तापूर्ण पहुंच मार्ग विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया। ग्राम केसरा में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि पर नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 4.61 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में महाविद्यालय का संचालन अस्थायी रूप से आईटीआई भवन में किया जा रहा है। कलेक्टर ने सन्ना में निमार्णाधीन महाविद्यालय भवन का भी निरीक्षण किया। लगभग 4 एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहे इस भवन के लिए लगभग 4.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

जैश क्राफ्ट के अंतर्गत 30 दिवसीय बांस एवं फर्नीचर निर्माण प्रशिक्षण का समापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर - जिला प्रशासन जशपुर द्वारा जैशक्राफ्ट ब्रांड के अंतर्गत ग्राम पंचायत झोलांगा के स्व-सहायता समूहों के 50 हितग्राहियों के लिए आयोजित 30 दिवसीय आवासीय बांस एवं फर्नीचर निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह शुक्रवार को लोखंडी स्थित महतारी सदन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, ग्राम पंचायत झोलांगा एवं लोखंडी के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं। जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुरी एवं बसोंढ़ समाज में सूपा, झोड़ा, टोकरी सहित विभिन्न बांस उत्पादों के निर्माण की समृद्ध परंपरा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक डिजाइन एवं बाजार की मांग के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि बांस से निर्मित सजावटी एवं उपयोगी उत्पादों की बाजार में व्यापक संभावनाएं हैं। जिला प्रशासन द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण एवं मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक डिजाइन, उन्नत बांस बुनाई तकनीक तथा मशीनों के माध्यम से कच्चे बांस के प्रसंस्करण एवं फर्नीचर निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि जैशक्राफ्ट के अंतर्गत बांस एवं फर्नीचर निर्माण के प्रथम चरण के प्रशिक्षण का उद्देश्य तुरी समाज की पारंपरिक बांस शिल्प कला को आधुनिक तकनीक एवं नवीन डिजाइनों से जोड़ना है, ताकि स्थानीय कारीगर बाजार की मांग के अनुरूप आकर्षक, गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर सकें। समारोह के दौरान सभी 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कलेक्टर रोहित व्यास ने मनोरा एवं सन्ना के विभिन्न विद्यालयों का किया निरीक्षण

शिक्षण व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा,जश लर्न के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया विशेष जोर

विद्यार्थियों से किया आत्मीय संवाद, विद्यार्थियों को आसान तरीके से पढ़ाया गणित का पाठ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर - नए शिक्षण सत्र की शुरूआत से ही विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री रोहित व्यास लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने मनोरा विकासखंड एवं सन्ना तहसील के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री व्यास ने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने जिले में कक्षा तीसरी से पांचवी तक के विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संक्रियाओं में दक्ष बनाने के उद्देश्य से संचालित जश लर्न कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर स्वयं भी शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं को सुना तथा खेल-खेल और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को सरल, रोचक एवं सहज तरीके से समझाया। विद्यार्थी भी कलेक्टर से मिलकर प्रसन्न नजर आए।

विद्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में गुटखा बिक्री पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई

कलेक्टर श्री व्यास ने मनोरा विकासखंड अंतर्गत शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला बेलटोली का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय एवं शौचालय की नियमित साफ-सफाई, बरसात के मौसम में परिसर को फिसलन मुक्त रखने तथा पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों से जश लर्न कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी लेते हुए चौटबोट गणिता ऐप का प्रभावी उपयोग करने तथा डैशबोर्ड में समयबद्ध जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही जश लर्न के लिए नियुक्त शैक्षिक संकुल समन्वयकों को तकनीकी सहयोग, नियमित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षा पांचवीं के छात्र शिवम महतो से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। छात्र ने आत्मविश्वास के साथ पूरा पहाड़ा सुनाया। इसके अलावा उन्होंने अन्य विद्यार्थियों से भी गणित के प्रारंभिक प्रश्न पूछे और उन्हें सरल एवं व्यवहारिक तरीके से हल करना सिखाया। कलेक्टर ने

विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया और खूब मेहनत करने को कहा। कलेक्टर ने शासकीय प्राथमिक शाला सरडीह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों को नियमित उपस्थिति दर्ज कर जिम्मेदारीपूर्वक शिक्षण कार्य करने तथा जश लर्न कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें व्यवहारिक तरीके से गणित के प्रश्न हल करना सिखाया तथा शिक्षकों को अध्ययन में कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देकर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को विद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं पान मसाला बिक्री की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को जप्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने दुकान संचालक से कहा कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों को व्यवहारिक एवं सरल तरीके से पढ़ाने पर दिया जोर

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने शासकीय प्राथमिक शाला चन्दाडीपा विकासखंड बगीचा का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने जश लर्न कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए शिक्षकों एवं शैक्षिक संकुल समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के पालकों से समय लेकर फोन पर संपर्क स्थापित करें। इससे पालकों से बेहतर समन्वय स्थापित होगा और सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से गणित की अवधारणाएं भी समझाईं। कलेक्टर ने शासकीय प्राथमिक शाला सरनाटोली, विकासखंड बगीचा का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचकर नियमित उपस्थिति दर्ज करने, अनुपस्थित विद्यार्थियों के पालकों से संपर्क स्थापित कर उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय में सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों को गतिविधि आधारित एवं व्यवहारिक तरीके से पढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि वे विषयों को आसानी से समझ सकें। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खेल-खेल में गणित के विभिन्न प्रश्न हल कराए और उन्हें सीखने के प्रति प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री विश्वास राव मस्के, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर रोहित व्यास ने आंगनबाड़ी केंद्र बेलटोली का का किया निरीक्षण

जशपुरनगर - कलेक्टर रोहित व्यास ने गुरुवार को विकासखंड मनोरा के आंगनबाड़ी केंद्र बेलटोली का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्र के नन्हे बच्चों ने कलेक्टर का पुष्प भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली एवं पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पोषण ट्रैकर में नियमित एवं समयबद्ध प्रविष्टि करने, बच्चों की अपार आईडी, आभा आईडी तथा टीकाकरण की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त और सभी योजनाओं का बेहतर संचालन के निर्देश दिए।

सम्पादकीय

संसद की गरिमा और मर्यादा सर्वोपरि

पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद से देश को ठोस समाधान और सार्थक बहस की अपेक्षा होती है। विपक्ष को सरकार से कठिन सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और सरकार को उनके जवाब देने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बहस का केंद्र असंसदीय शब्दों और आरोप-प्रत्यारोप पर आ जाता है, तो मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। संसद में विचारों का संघर्ष लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन शब्दों का संयम उसकी गरिमा और मर्यादा ही सदन की नींव है। बुधवार को लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक पर हुई बहस इसी सवाल को फिर से सामने ले आई। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगभग 50 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अपने भाषण में 'इडियट' और 'अंधभक्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार हस्तक्षेप करते हुए इसे संसदीय मर्यादा के विपरीत बताया और माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप करते हुए आपत्तिजनक माने गए शब्दों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष द्वारा आपत्तिजनक माने गए शब्दों को कार्यवाही से हटाना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। अंततः लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि मतभेद कितने भी गहरे हों, संवाद शालीन, तथ्यपरक और मर्यादित बना रहे। बहस के दौरान गृह मंत्री पर छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने का आरोप भी लगाया गया, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज किया। ऐसे गंभीर आरोपों की जांच और सत्यापन तथ्यों तथा कानून के आधार पर होनी चाहिए। संसद में बोले गए शब्द केवल तत्कालीन बहस तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे देश की लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी शब्द की स्थायी 'प्रतिबंधित सूची' नहीं होती। किसी टिप्पणी को असंसदीय माना जाएगा या नहीं, इसका निर्णय उसके संदर्भ, प्रभाव और सदन की गरिमा के आधार पर अध्यक्ष या सभापति करते हैं। यही कारण है कि समय-समय पर विभिन्न शब्द कार्यवाही से हटाए जाते रहे हैं। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संसद की संस्थागत गरिमा को बनाए रखने के लिए होती है। आज देश के करोड़ों युवा संसद की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीर बहस हो, ठोस नीतियां बनें और समाधान निकले। यदि चर्चा का केंद्र असंसदीय शब्द, नारे और राजनीतिक टकराव बन जाए, तो सबसे अधिक निराशा उन्हीं युवाओं को होती है, जिनके हितों की रक्षा के लिए संसद अस्तित्व में है। लोकतंत्र की शक्ति सत्ता और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी से बढ़ती है। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार से कठिन और असहज प्रश्न पूछे, जबकि सरकार का दायित्व है कि वह तथ्यों और जवाबदेही के साथ उनका उत्तर दे। लेकिन दोनों पक्षों की समान जिम्मेदारी यह भी है कि संसद की गरिमा और मर्यादा किसी भी राजनीतिक संघर्ष से ऊपर रहे। मतभेद जितने भी तीखे हों, संवाद तथ्यपरक, संयमित और जनहित केंद्रित होने चाहिए और सभी दल यह ध्यान रखें की सदन की गरिमा और मर्यादा सर्वोपरि है, इसे बनाए रखना सबका दायित्व है।

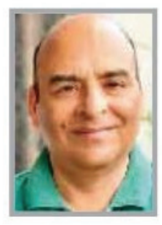

मुद्दा
पंकज चतुर्वेदी

विकास कार्यों की जवाबदेही भी तय हो

ऐसा क्यों होता है कि बरसात आते ही देश के विकास के प्रतिमान ढहने लगते हैं। कई हजार करोड़ की संरचनाएं तकनीकी कारणों से जानलेवा बन जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में राजमार्गों का जाल बिछ रहा है, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाएं शुरू हो रही हैं, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, समुद्र पर लंबे पुल तैयार हो रहे हैं और स्मार्ट शहरों का सपना आकार ले रहा है। इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। नई बनी सड़कों का पहली बारिश में उखड़ जाना, उद्घाटन के कुछ समय बाद ही पुलों में दरारें आना, निर्माणाधीन पुलों का गिरना, सार्वजनिक इमारतों की छतों का ढह जाना गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

आखिर ऐसा क्यों होता है कि बरसात आते ही देश के विकास के प्रतिमान ढहने लगते हैं। कई हजार करोड़ की संरचनाएं तकनीकी कारणों से जानलेवा बन जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में राजमार्गों का जाल बिछ रहा है, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाएं शुरू हो रही हैं, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, समुद्र पर लंबे पुल तैयार हो रहे हैं और स्मार्ट शहरों का सपना आकार ले रहा है। सरकारें इन परियोजनाओं को नए भारत की पहचान के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस चमकदार तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पिछले कुछ वर्षों में नई बनी सड़कों का पहली बारिश में उखड़ जाना, उद्घाटन के कुछ समय बाद ही पुलों में दरारें आना, निर्माणाधीन पुलों का गिर जाना और सार्वजनिक इमारतों की छतों का ढह जाना एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है-क्या हम टिकाऊ विकास कर रहे हैं या केवल विकास का प्रदर्शन?

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे हो या फिर प्रगति मैदान की सुरंग, बरसात में जलजमाव होना आम बात है। बिहार में गंगा पार का अगुवानी–सुल्तानगंज पुल निर्माण के दौरान दो बार ढह गया। इस परियोजना पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। इसके बावजूद लंबे समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि डिजाइन में कमी थी, निर्माण सामग्री दोषपूर्ण थी या निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई। इसी प्रकार, बिहार में कई छोटे पुलों और पुलियों के लगातार गिरने की घटनाओं ने राज्य की निर्माण व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना भी केवल एक तकनीकी विफलता नहीं था। करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित प्रतिमा का अपेक्षाकृत कम समय में ढह जाना यह बताता है कि गुणवत्ता परीक्षण और संरचनात्मक सुरक्षा के मानकों की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के कुछ ही समय बाद उन्नाव के निकट इसकी लिंक रोड पहली ही बारिश में धंस गई। पहली ही भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर के पास 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (विशेषकर हाथ कररोड़ा गांव के समीप) कई जगहों से धंस गया था। इसके कारण बने बड़े-बड़े गड्ढों से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश दुर्घटनाओं के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, जांच समिति बनती है, कुछ अधिकारियों का तबादला या निलंबन होता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। दोष तय नहीं होता, न किसी बड़ी निर्माण एजेंसी की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और न ही ऐसी घटनाओं से सीख लेकर व्यवस्था में व्यापक सुधार दिखाई देता है। ऐसी घटनाएं केवल इंजीनियरिंग की विफलता नहीं हैं। इनके पीछे कई स्तरों की समस्याएं काम करती हैं। पहली समस्या है समय से पहले परियोजना पूरी करने का राजनीतिक दबाव। आज अधिकांश बड़ी परियोजनाएं चुनावी कैलेंडर से जुड़ जाती हैं। उद्घाटन की तारीख तय हो जाती है और फिर निर्माण एजेंसियों पर समय सीमा पूरी करने का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में गुणवत्ता परीक्षण, अंतिम निरीक्षण और तकनीकी मानकों के पालन में समझौते की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी समस्या है सबसे कम बोली आधारित

ठेका प्रणाली। सरकारी खरीद में कम लागत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा केवल सबसे सस्ता ठेका पाने तक सीमित रह जाए तो गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है। कई बार ठेकेदार बाद में लागत की भरपाई घटिया सामग्री, कम गुणवत्ता वाले श्रम या तकनीकी मानकों में कटौती करके करते हैं। तीसरी और सबसे गंभीर समस्या है जवाबदेही का अभाव। किसी पुल के गिरने, सड़क के धंसने या सरकारी भवन के ढहने के बाद यदि दोषी इंजीनियर, निर्माण एजेंसी या निगरानी संस्था पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो यह संदेश जाता है कि सार्वजनिक धन की बर्बादी की कोई वास्तविक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि गलतियां दोहराई जाती हैं। विडंबना यह है कि भारत में परियोजनाओं की सफलता का मूल्यांकन अक्सर उनकी लागत, लंबाई या उद्घाटन की तारीख से किया जाता है, न कि उनकी डिजाइन आयु और टिकाऊपन से। यदि किसी पुल की अनुमानित आयु सौ वर्ष है, लेकिन वह दस वर्ष में ही बड़ी मरम्मत मांगने लगे, तो उसे सफल परियोजना नहीं कहा जा सकता, चाहे उसका उद्घाटन कितने ही भव्य तरीके से हुआ हो। जलवायु परिवर्तन का तर्क भी अक्सर सामने रखा जाता है। निश्चित रूप से अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन यदि विकसित देशों में इन्हीं परिस्थितियों में बने पुल और सड़कें दशकों तक सुरक्षित रह सकती हैं, तो भारत में हर बार प्राकृतिक आपदा को ही दोष नहीं दिया जा सकता। आधुनिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य ही बदलती जलवायु को ध्यान में रखकर संरचनाएं तैयार करना है। इस समस्या का एक सामाजिक पक्ष भी है। जब किसी सड़क के बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो उसकी वास्तविक लागत कई गुना बढ़ जाती है। इसका भुगतान अंततः करदाता करता है। दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि अलग होती है। खराब आधारभूत संरचना उद्योग, पर्यटन, परिवहन और निवेश-सभी को प्रभावित करती है। इसलिए यह केवल तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और नागरिक सुरक्षा का प्रश्न भी है। समाधान भी स्पष्ट हैं, बशर्ते उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। प्रत्येक बड़ी परियोजना का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष गुणवत्ता ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। निर्माण पूरा होने के बाद केवल उद्घाटन नहीं, बल्कि विस्तृत सुरक्षा प्रमाणन सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था वास्तव में लागू होनी चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्टों पर समयबद्ध कार्रवाई हो। साथ ही, परियोजनाओं की पूरी जानकारी-लागत, ठेकेदार, गुणवत्ता परीक्षण और रखरखाव-जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। भारत को विकास की गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास की गति और गुणवत्ता दोनों साथ चलें। दुनिया में किसी भी देश की पहचान केवल ऊंची इमारतों, लंबे पुलों या चौड़ी सड़कों से नहीं बनती, बल्कि उनसे बनती है जो दशकों तक सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद बनी रहें। यदि हम हर दुर्घटना के बाद केवल शोक व्यक्त करेंगे, मुआवजा घोषित करेंगे और फिर अगली दुर्घटना की प्रतीक्षा करेंगे, तो यह विकास नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की निरंतर बर्बादी होगी। अब समय आ गया है कि भारत में आधारभूत संरचना का मूल्यांकन केवल उसकी संख्या से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, टिकाऊपन और जवाबदेही से किया जाए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसके उद्घाटनों में नहीं, बल्कि उन संरचनाओं में होती है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित खड़ी रहती हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शिक्षा व्यवस्था
अजय जैन

शिक्षा व्यापार नहीं, राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च साधन

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चला छात्रों का आंदोलन केवल प्रश्नपत्र लीक होने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं की उस पीड़ा, निराशा और आक्रोश का प्रतीक रहा है, जिनके सपने बार-बार एक भ्रष्ट और असफल व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का लगातार लीक होना आज देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका है। प्रत्येक प्रश्नपत्र लीक केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत, समय और धन इस आशा में लगाया कि उन्हें योग्यता के आधार पर अवसर मिलेगा। इस समस्या का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है। यह विद्यार्थियों और उनके परिवारों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ देता है। देश के दूर-दराज गांवों से आने वाले छात्रों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें दिल्ली, कोटा, हैदराबाद और अन्य महानगरों में आना पड़ता है। वे अत्यंत छोटे, भीड़भाड़ वाले कमरों में अमानवीय परिस्थितियों में रहने को विवश होते हैं। देश अभी भी उन दर्दनाक घटनाओं को नहीं भूला है, जब पिछले वर्ष बाढ़ के कारण कई छात्रों की जान चली गई थी। समय-समय पर कोचिंग संस्थानों में आग लगने जैसी घटनाओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इससे भी अधिक दुखद यह है कि अनेक छात्र प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षाएं निरस्त होने या बार-बार स्थगित होने के कारण गहरे अवसाद में चले जाते हैं। कुछ छात्र आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाने तक को विवश हो जाते हैं। हर बार परीक्षा रद्द होने का अर्थ है-फिर से तैयारी, फिर से कोचिंग फीस, फिर से किराया, भोजन और जीवन-यापन का खर्च। यह बोझ उन माता-पिताओं के लिए असहनीय हो जाता है, जो अपनी सीमित आय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की प्रमुख मांग तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। व्यापक जनाक्रोश और छात्रों के दबाव के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है-क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफे से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भविष्य में कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं होगा? उत्तर स्पष्ट है-नहीं। समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तथा आधुनिक डिजिटल सुरक्षा तकनीकों का युग है। भारत के पास ऐसी तकनीकी क्षमता उपलब्ध है जिससे लगभग पूर्णतः सुरक्षित परीक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है। आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और संस्थागत जवाबदेही की है। दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रायः तात्कालिक राजनीतिक लाभ-हानि में उलझे रहते हैं, जबकि समस्या कहीं अधिक गहरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई दशकों में विभिन्न सरकारों के कार्यकाल के दौरान एक संगठित 'शिक्षा माफिया' विकसित हो गया है, जिसने शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि व्यापार बना दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा धीरे-धीरे सामान्य नागरिक की पहुंच से बाहर होती जा रही है। एक समय था जब प्री-मेडिकल, प्री-इंजीनियरिंग अथवा विद्यालयी शिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार होती थी और उसी के आधार पर व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश मिलता था। आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। हजारों छात्र ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में केवल 'डमी एडमिशन' लेकर अपना अधिकांश समय महंगे कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। आज आवश्यकता सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। भर्ती परीक्षाओं को अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षित बनाया जाए, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो तथा गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाया जाए। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों के प्रभावी नियमन तथा योग्यता-आधारित प्रवेश प्रणाली को पुनः स्थापित करना समय की मांग है। शिक्षा को व्यापार नहीं, राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च साधन माना जाना चाहिए। हमें अपनी उस पुरानी परंपरा की ओर लौटना होगा, जहां शिक्षा को एक पवित्र दायित्व समझा जाता था, न कि लाभ कमाने का माध्यम। यदि हम केवल मंत्रियों के इस्तीफों तक सीमित रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो करोड़ों युवाओं का भविष्य बार-बार इसी प्रकार अनिश्चितता, निराशा और अन्याय का शिकार होता रहेगा।

(लेखक पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य

संकलित
दर्शन

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के तीन -ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग में सांख्य की सहायता से मनुष्य तर्क-वितर्क द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु अक्सर तर्क-वितर्क में वह अपने मार्ग से भटक जाता है। कर्म मार्ग में भी मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना होता है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी भटकने की पूरी संभावना होती है। वहीं भक्ति मार्ग में वह अपने आप को पूर्णतया ईश्वर भक्ति में समर्पित कर देता है। वह स्वयं को विचलित नहीं करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर प्राप्ति की पूरी संभावना होती है। इन तीनों मार्गों पर चलकर सफल होने के लिए मनुष्य को अष्टांग योग के पहले दो चरणों को जीवन में अपनाना जरूरी है। यह हैं यम और नियम। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं। सत्य शब्द से तात्पर्य है सत्यता का जीवन में हर समय पालन करना। अहिंसा केवल जीव हिंसा से ही संबंधित नहीं है, इसमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना भी आता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आवश्यकता से ज्यादा किसी वस्तु या धन का संग्रह न करना। वहीं नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान आते हैं। शौच से मतलब मन की सफाई होता है। इसके लिए मनुष्य को स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। यम और नियम को जीवन में अपनाने के लिए सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी है।

पति-पत्नी के बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए

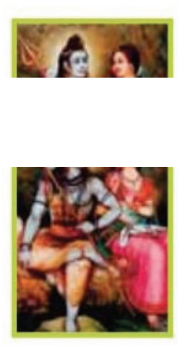

संकलित
प्रेरणा

शिव जी और सती को रास्ते में श्रीराम दिखाई दिए। श्रीराम सीता के वियोग में रो रहे थे। शिव जी ने श्रीराम को दूर से ही प्रणाम किया और देवी सती से कहा कि तुम भी भगवान को प्रणाम करो। सती ने सोचा कि जो व्यक्ति रो रहा है, वह भगवान कैसे हो सकता है। शिव जी ने समझाया कि आप श्रीराम पर संदेह न करें, वे भगवान ही हैं। शिव जी तो वहां से चले गए, लेकिन देवी सती ने सोचा कि वे श्रीराम की परीक्षा लेंगी। ऐसा सोचकर वे सीता का रूप धारण करके श्रीराम के सामने पहुंच गईं। श्रीराम ने उन्हें पहचान लिया, प्रणाम किया और पूछा कि देवी आप अकेली आई हैं, भगवान शिव कहां हैं। श्रीराम की बात सुनकर सती लज्जित हो गईं और चुपचाप शिव जी के पास लौट आईं। इसके बाद शिव जी ने देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया था। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में दक्ष ने शिव-सती को छोड़कर सभी देवी-देवताओं को बुलाया था। जब ये बात सती को मालूम हुई तो उन्होंने शिव जी से पिता के यहां जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने सती को समझाया कि हमें ऐसे आयोजन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और पिता के यहां यज्ञ में चली गईं। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने सती के सामने ही शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। सती ये सहन नहीं सकीं और यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दी।

करतब

इंफाल। खुमान लम्पक मुख्य स्टेडियम में 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के उद्घाटन समारोह के दौरान कलाकार कलाबाजी और आग उगलने का प्रदर्शन करते हुए।

आज की पाती

अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग न हो

लोकतंत्रीय व्यवस्था में संविधान के अनुसार हर नागरिक को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्ति/प्रदर्शन व अहिंसक/ शांतिपूर्ण मार्च का अधिकार दिया गया है। किन्तु उसका बेजा उपयोग या दुरुपयोग कानूनी जुर्म होगा। अगर अभिव्यक्ति/प्रदर्शन अहिंसक और शांतिपूर्ण है तो सरकारी कानून-व्यवस्था का अनावश्यक उपयोग भी संविधान के अनुसार गैरकानूनी माना जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में पेपर लीक के मामले में सीजेपी द्वारा छात्रों को लेकर अहिंसक प्रदर्शन/आंदोलन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संज्ञान लेते हुए यही कहा है कि प्रदर्शनकारी हों या पुलिस, यदि किसी ने भी किसी पर अनावश्यक ज्यादती की है तो वे कानून के दायरे में आएंगे। – *संजय द्विवेदी, हिसार*

ट्रेंड

परीक्षा संशोधन विधेयक

लोकसभा ने व्यापक बहस के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह भारत की परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **राजनाथ सिंह**, रक्षामंत्री

हर छात्र का अपमान

रेपिस्ट का बचाव करने वाले व्यक्ति से ज्यादा घटिया और कोई नहीं हो सकता। प्रह्लाद जोशी हमारे शिक्षा तंत्र और उसमें पढ़ने वाले हर छात्र का अपमान हैं। उनके अधीन संस्थानों में करोड़ों युवतियां पढ़ती हैं। भारत की महिलाएं पीएम मोदी के नए शिक्षा मंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगी।
- **राहुल गांधी**, सांसद, कांग्रेस

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 69 किलोग्राम भारोत्तोलन इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर हरजिंदर कौर और पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने पर गुलवीर सिंह को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
- **नीतीश कुमार**, राज्यसभा सांसद, जदयू

शिक्षा विभाग में खाली पद

बीजेपी ने अपने 'संकल्प पत्र 2023' के पेज 33 पर लिखित रूप में वादा किया था: "हम शिक्षा विभाग में सभी खाली पदों को एक साल के भीतर भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" आज शिक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या बढ़कर लगभग डेढ़ लाख हो गई है।
- **अशोक गहलोत**, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

पीओके के प्रदर्शनकारी पाक के दुश्मन : रक्षा मंत्री आसिफ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह दुश्मन बताते हुए कहा है कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इस बीच, पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 20 हो गई। प्रतिबंधित ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) ने बुधवार को कहा कि सोमवार से पीओके में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ हुई झड़पों में उसके कम से कम 20 कार्यकर्ता मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। हालांकि, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मृतकों की संख्या पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, 'प्रदर्शनकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मैं उन्हें भारत की ही श्रेणी में मानता हूं और उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूं।' वहीं, प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जेएएसी ने उनके साथ एक बैठक की थी और अपनी 38 मांगें रखी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद और मीरपुर पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं।

ऑफ बीट

भाषाओं को खत्म कर रहा जलवायु परिवर्तन

अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के केलर में रहने वाली पॉलिन स्टेन्सगर का दो मई 2023 में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनके साथ उनकी भाषा भी खत्म हो गई। पॉलिन 'इन-हा- उम-चीन' भाषा बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। वॉशिंगटन राज्य क्षेत्र में अमेरिका के रहने वाले कुछ समूह इस भाषा में बात किया करते थे। पॉलिन के अपनी भाषा के प्रति प्यार को धन्यवाद, जिसकी वजह से हम इस भाषा से पूरी तरह अनजान नहीं हैं। सैलिश स्कूल ऑफ स्पोकाने के प्रधानाचार्य क्रिस्टॉफर पार्किन ने बताया कि पॉलिन स्टेन्सगर ने छह पाठ्यपुस्तकों की रचना की और उनके पास भाषा की 100 से ज्यादा रिकॉर्डिंग हैं। अगर कोई भी 'इन-हा-उम-चीन' सीखना चाहता है तो वह सीख सकता है। लेकिन कुछ विलुप्त भाषाएं, 'इन-हा-उम-चीन' जितनी भाग्यशाली नहीं हैं। हम इन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से भाषाओं के संदर्भ में समृद्ध हैं लेकिन वहां लाखों लोग पर्यावरणीय आपदाओं के चलते विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं, जो भाषाओं के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण है। दुनियाभर में आज सात हजार से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका इतिहास है और इन्हें बोलने वालों के पास इनका ज्ञान भंडार है।

खबर संक्षेप

रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 8 की मौत

कीव। रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 8 नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के कई इलाकों में हुआ, जिनमें पोलैंड सीमा के पास के क्षेत्र भी शामिल हैं। हमले के बाद पोलैंड ने जांच शुरू की कि क्या रूस की एक क्रूज मिसाइल उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कम से कम 10 क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे दर्जनों घर, कारोबारी प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।

ऑस्ट्रेलिया ने भी दिखाई टेलीग्राम पर सख्ती

मेलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वीडियो और पोस्ट को न हटाने के मामले को लेकर कानूनी मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर (ई-कमिश्नर) ने टेलीग्राम पर आरोप लगाया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से 'आतंकवाद का समर्थन' करने वाले पोस्ट और वीडियो हटाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। रेगुलेटर के मुताबिक, इस लापरवाही के लिए कंपनी पर 54.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऑल्टमैन बोले- एआई को धीमा करना होगा

वॉशिंगटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों और स्वायत्त सिस्टम की क्षमताओं को देखते हुए सैम

ऑल्टमैन ने पहली बार स्वीकार किया है कि भविष्य में एआई के विकास की गति को नियंत्रित करना जरूरी हो सकता है, ताकि समाज इस तकनीक के साथ सुरक्षित तरीके से तालमेल बिठा सके। ओपनएआई और एंथ्रोपिक के 1,100 से अधिक कर्मचारियों ने पेसिंग द फ्रंटीयर नाम की एक याचिका का समर्थन किया है।

होर्मुज संकट पर एक्शन मोड में सरकार!

पीएम मोदी ने मंत्रियों संग की समीक्षा बैठक कहा- जनता व किसान को नहीं हो दिक्कत

पीएम नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

> पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हर भारतीय नाविक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी

ऊर्जा, कृषि, व्यापार, सुरक्षा पर हो नियमित समीक्षा

सरकार वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद की उपलब्धता, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और निर्यात पर पड़ने वाले असर जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

पीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में आम लोगों और किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हर भारतीय नाविक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारतीय जहाज पर तैनात हैं या किसी विदेशी जहाज पर। जरूरत पड़ने पर सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

पीएम की फेसबुक पोस्ट मामला सरकार ने मेटा से मांगा विस्तृत जवाब

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार के सामने पेश होकर पीएम नरेंद्र मोदी की उस पोस्ट के लिए विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिस पर कुछ समय के लिए फेसबुक ने अस्थाई रोक लगा दी थी। यह बैठक अगले 7 से 10 दिनों के बीच हो सकती है। इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि सरकार मामले को पूरी तरह से समझने के लिए मेटा से नीतिगत स्तर और तकनीकी स्तर दोनों प्रकार का स्पष्टीकरण लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी चिंताएं सीधे मेटा तक पहुंचाना चाहता है और उन हालात के बारे में पूरी जानकारी चाहता है जिनकी वजह से यह अस्थायी रोक लगाई गई थी। कृष्णन ने बताया कि मेटा ने इस घटना पर पहले ही खेद जताया है और सरकार को शुरुआती स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है।

निर्यातकों को राहत देने पर चर्चा

होर्मुज संकट का असर भारत के निर्यात कारोबार पर भी पड़ सकता है। इसी को देखते हुए बैठक में निर्यातकों को राहत देने के संभावित उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर इस संकट के प्रभाव का भी आकलन किया गया। सरकार ने संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि वह वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऊर्जा, कृषि, व्यापार और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी चुनौती का समय रहते प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

आपूर्ति निरंतर बनी हुई

कैबिनेट सचिव ने सीसीएस को मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त बनी हुई है। कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर पा रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है।

पीएनजी का उपयोग बढ़ाएं

पीएम ने देश में पीएनजी के इस्तेमाल को और तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि ऊर्जा आपूर्ति मजबूत बनी रहे और किसी भी संभावित संकट का असर कम किया जा सके। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, सौर ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन वाले अन्य स्रोतों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर जोर दिया जाना चाहिए।

खाद का रिजर्व तैयार करें

बैठक में कृषि क्षेत्र की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पीएम को बताया कि अगली रबी फसल के लिए पर्याप्त खाद का भंडार उपलब्ध है। साथ ही 2027 की खरीफ फसल के लिए भी खाद का रिजर्व तैयार करने का काम जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को किसी भी तरह की खाद की कमी का सामना न करना पड़े।

कोयंबटूर बम धमाका मामला

जांच में ईडी ने की 3 राज्यों में 16 स्थानों पर 'छापेमारी'

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तीन राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई वर्ष 2022 में कोयंबटूर में हुए आईएसआईएस से प्रेरित कार बम धमाके के लिए कथित तौर पर जुटाई गई आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई।

- ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया

अधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, तेलंगाना के हैदराबाद तथा महाराष्ट्र के मुंबई में कुल 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित

ईडी के मुताबिक, आरोपियों को कोवई अरबी कॉलेज के प्रमोटर जमील बाशा ने मार्गदर्शन दिया। यह हमला जेमेशा मुबीन और उसके अन्य साथियों ने आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर अंजाम दिया था। इसके लिए विस्फोटकों से भरी एक मॉडिफाइड कार का इस्तेमाल किया गया था। आरोपियों ने अपनी कथित आतंकी गतिविधियों के लिए दो तरीकों से धन जुटाया। पहला, कोविड-19 महामारी के दौरान फर्जी वैक्सीन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का नेटवर्क चलाकर और दूसरा, कोयंबटूर के कोवई अरबी कॉलेज में कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले निवेश (डोनेशन) के माध्यम से।

गैस से लदे दो जहाजों में आग लगी

ईरान ने मिस्त्र के दमियाता पोर्ट पर किया ड्रोन हमला

वॉशिंगटन डीसी/ तेहरान/ तेल अवीव (एजेंसी) ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग अब मिस्त्र तक पहुंच गई है। मिस्त्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को दमियाता पोर्ट पर दो गैस टैंकरों में लगी आग हादसा नहीं, बल्कि ड्रोन हमले का नतीजा थी। ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के नैचुरल गैस स्टोरेज टैंकर एनरगोस विंटर को निशाना बनाया, जिसके बाद आग पास में खड़े दूसरे टैंकर गैसलॉग सलेम तक फैल गई। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। हमले का मकसद यह मैसेज देना था कि अगर जंग और बढ़ी तो दुनिया की समुद्री शिपिंग और एनर्जी सप्लाई भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर हमले करने की चेतावनी दी है। उधर, कुवैत में चीनी कंपनी पर ईरान के हमला में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

चीन-भारत के बीच बढ़ेंगे संबंध

कल से खुलेगा परंपरागत बार्टर ट्रेड, खच्चरों से होगी माल ढुलाई

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे से होकर परंपरागत बार्टर-ट्रेड (सामान के बदले सामान) रूट 1 अगस्त से फिर से खुलने वाला है। भारत-चीन सीमा पर 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह व्यापार मार्ग पिछले 6 वर्षों से बंद पड़ा है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित यह क्षेत्र भारत और तिब्बत के

शिपकी ला दर्रा

बीच परंपरागत व्यापार मार्ग रहा है। पहले यह मार्ग इस साल 1 जून से ही खुलने वाला था, लेकिन इमिग्रेशन से जुड़ी औपचारिकताओं की वजह से इसमें दो महीने की देरी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

भोजशाला परिसर से सटी जगह पर नमाज पढ़ने की मिली मंजूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला विवाद में अपने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के

लिए भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन खसरा नंबर 596 पर अनुमति दी है। यह परिसर के पीछे दाहिनी ओर निकलने वाले वैकल्पिक निकास मार्ग के ठीक सामने है। यहां हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस भूखंड तक पहुंचने के लिए अलग रास्ता है और यह विवादित भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास है। इसलिए यह नमाज के लिए उपयुक्त स्थान है।

'येलो साइट' नमाज के लिए सूटेबल

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नक्शे में

दिखाई गई 'येलो साइट' पर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने कहा कि इस जगह तक अलग और स्वतंत्र रास्ता है। यह विवादित परिसर से सटी हुई है। मुस्लिम पक्ष ने भी इसी जगह पर सहमति जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'सिर्फ कानून-व्यवस्था की आशंका के आधार पर लोगों के धार्मिक अधिकार नहीं रोके जा सकते।

भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का कार्यकाल पूरा

कहा- दोनों देशों के बीच सबमरीन समझौते पर बहुत जल्द होगी डील

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत में जर्मनी के राजदूत

फिलिप एकरमैन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस बीच राजदूत फिलिप ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच जल्द ही सबमरीन समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबमरीन डील को लेकर मैं बहुत आशावान और आश्वस्त हूं कि यह बहुत जल्द, शायद अगले महीने तक, साइन हो जाएगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा

राजदूत फिलिप एकरमैन व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर

राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि पीएम हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सक्रिय साझेदार रहे हैं। हमने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो इस द्विपक्षीय संबंध में वास्तव में बहुत रुचि रखते हैं, और मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने फेडरल चांसलर को निमंत्रित किया है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जर्मनी के राजदूत एकरमैन से मुलाकात की थी।

जर्मनी यूरोप में भारत का बड़ा साझेदार

एकरमैन ने कहा कि जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका हर साल 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम है। यह बिजनेस के लिहाज से भारत के सबसे जरूरी साझेदारों में से एक है।

मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

सोनभद्र। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 05 अगस्त, 2026 कर दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित थी। सहायक निदेशक मत्स्य आधिकारी शुभम कश्यप ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं, अंतदेर्शीय खारे जल क्षेत्रों में नवीन तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनाओं का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख एवं दिशा-निर्देश विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। जनपद के मत्स्य पालकों, मत्स्य कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय से अपना आवेदन अवश्य करें।

पालघर के तटीय क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा दीवारों के लिए 122.26 करोड़ की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पालघर। पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सावरा ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पालघर जिले के तटीय गांवों में आपदा न्यूनीकरण योजना के तहत समुद्री सुरक्षा दीवारों (सी वॉल) के निर्माण के लिए 122.26 करोड़ के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने और केंद्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने 29 जुलाई को नई दिल्ली में गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा ।सांसद डॉ. सावरा ने बताया कि पालघर जिले की करीब 110 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा हर वर्ष समुद्री कटाव, ऊंची लहरों, ज्वार और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है। इसके कारण समुद्र का पानी तटीय गांवों में घुस जाता है, जिससे लोगों के घर, खेती, बाग-बगीचे, सड़कें और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों की आजीविका लगातार खतरे में है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है ।उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में पालघर जिले के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा दीवारों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में पालघर और दहानू तहसील के सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 कार्य शामिल हैं

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अविनाश मित्तल आ. रोशन लाल मित्तल, उम्र 37 वर्ष, जाति अग्रवाल निवासी पैलेश मार्ग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के द्वारा अनावेदक श्री रामअवतार बंसल आ. श्री धनीराम अग्रवाल, उम्र 58 वर्ष निवासी मयुरध्वज अपार्टमेंट एकटेशन पटपरगंज, दिल्ली के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 09 मोहल्ला बाबूपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3467/4866/353 रकबा 1280 वर्गफीट भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 30/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका बसंत साहू आ०/पति स्व० करमन साव जाति तेली, निवासी चांदनी चौक मायापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मायापुर, शीट नम्बर-6 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2194/3, 2196/3 रकबा 0.10 1/2, 0.05 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 11/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं गोपाल कुमर नाग (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र /सुपुत्री/पत्नी नन्द कुमार नाग, शहर / गाँव- गल्हापारा बहामा, तहसील- लैलूंगा, जिला रायगढ छत्तीसगढ़ ने अपना नाम गोपाल कुमर नाग (पुराना नाम) से बदल कर गोपाल नाग. (नया नाम) रख लिया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं कान्हा अग्रवाल पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी बजरंगलाल अग्रवाल. गाँव / शहर लुडेग तहसील- पत्थगाँव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम- कान्हा अग्रवाल (पुराना नाम) से बदल कर आर्यन अग्रवाल (नया नाम) रख लिया है। मैं बजरंगलाल अग्रवाल (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र /सुपुत्री- बलकुंद अग्रवाल गाँव/शहर लुडेग, तहसील- पत्थगाँव, जिला- जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम कान्हा अग्रवाल (पुराना नाम) से बदल कर आर्यन अग्रवाल (नया नाम) रख लिया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० /अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अविनाश मित्तल आ० रोशन लाल मित्तल, जाति अग्रवाल, निवासी पैलेस मार्ग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-11 क मोहल्ला सदर रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4817/59 रकबा 975 वर्गफीट भूमि को बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मय मेंन्टनेश खसरा की प्रतिलिपि सहित पेश किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 23/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क०-/अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लक्ष्मी सिंह आ. राजेश सिंह एवं माता स्व. श्रीमती सरोज, निवासी दरीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम मेंण्ड्राखुर्द स्थित भूमि खसरा न0 399, 400, 684, 585/1. 586/1, 595 कुल खसरा नंबर 06 कुल रकबा 0.992 हे० भूमि का अनावेदिका चन्द्रमणी आ. स्व. गेंदाराम पत्नी श्री कुदंन राम, निवासी जोड़ा पीपल के पास केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के मध्य खाता विभाजन कराने बावत आवेदन छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 31/08 /2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा जायेगा । आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया आज दिनांक 30/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

873094न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सुखराम सिंह आ०/पति बदन सिंह जाति निवासी आ०क०सी रा०प० कॉलोनी बीहीबाड़ी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-पोस्ट ऑफिस रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/49 रकबा 60 वर्गमीटर भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 05/08/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 22/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० //अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अशोक कुमार अग्रवाल आ० गनपत राम अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर 09 मोहल्ला - बाबूपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3467/4866/327 रकबा 1750 वर्गफीट भूमि को अनावेदिका / केता- राधा अग्रवाल पति पीताम्बर लाल अग्रवाल, निवासी प्रतापगढ़, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा प्रतिलिपि सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।आज दिनांकः- 21/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

चौपाटी में स्थायी अतिक्रमण से भड़के ठेला व्यवसायी

कलेक्टर से लेकर शहर सरकार तक शिकायत, कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शहर के हृदय स्थल पुराने बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के पीछे संचालित अस्थाई चौपाटी में एक स्थायी गुमटी रखे जाने के बाद वर्षों से यहां ठेलों के माध्यम से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। अपने रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित सभी ठेला व्यवसायी एकजुट होकर कलेक्टर, नगर पालिका अध्यक्ष तथा नपा सीएमओ व वार्ड पार्षद को शिकायत पत्र सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से शासन और नगर पालिका द्वारा तय व्यवस्था के अनुरूप अस्थायी ठेलों के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं। प्रतिदिन कारोबार समाप्त होने के बाद सभी अपने-अपने ठेले घर ले जाते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थल पर स्थायी कब्जा नहीं होता। इसी व्यवस्था के कारण चौपाटी अब तक व्यवस्थित रूप से संचालित होती रही है। शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा लगभग 144 वर्गफीट लोहे की स्थायी गुमटी चौपाटी परिसर में रख दी गई है। इससे न केवल चौपाटी की व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि अन्य लोगों को भी स्थायी कब्जा करने का रास्ता मिल गया है। व्यवसायियों का कहना है कि यदि अभी इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में पूरी चौपाटी स्थायी अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगी और वर्षों से मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे छोटे व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। जिला चौपाटी संघ के सभी ठेला व्यवसायियों ने सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर श्रीमती रैना जमील, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनीष गायकवाड़ व वॉर्ड पार्षद गैबिनाथ साहू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि चौपाटी में रखी गई स्थायी गुमटी को तत्काल हटाया जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के स्थायी अतिक्रमण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि सभी व्यवसायियों को एक समान अवसर मिल सके और चौपाटी की मूल व्यवस्था बनी रहे। छोटे व्यवसायियों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ वर्षों से चली आ रही समान व्यवस्था को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन और नगर पालिका इस सामूहिक शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या चौपाटी को स्थायी अतिक्रमण से बचाने के लिए समय रहते ठोस कार्रवाई की जाती है।

शहर में लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण, नपा उदासीन

यह विवाद केवल चौपाटी तक सीमित नहीं है। शहर के कई प्रमुख चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्रों में भी अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। नगर पालिका की उदासीनता के कारण सड़कें संकरी होती जा रही हैं, यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और शहर की सुंदरता भी धूमिल पड़ रही है। जब हालात बिगड़ते हैं, तब अतिरिक्त जिम्मेदारी यातायात पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस के कंधों पर आ जाती है, जबकि अतिक्रमण रोकना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदीप अग्रवाल, गोविंद कुशवाहा, रवि कुशवाहा, विकास अग्रवाल, सुशील थापा, शिव प्रकाश, प्रदीप कुशवाहा, रतनलाल मेवाड़, राकेश कुशवाहा, झलर मिश्रा, विनित मिश्रा, मलखान सिंह, जगत थापा, दीपक अग्रवाल, गौतम, शंकर मद्रासी, संजय जायसवाल, कमलेश साहू, गुलाब गुप्ता, राजा बाबू साहू, श्रीमति सुनीता गुप्ता सहित जिला चौपाटी संघ सूरजपुर के सभी व्यवसाई उपस्थित रहे।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम- शिवनाथ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भाजपा जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री शिव नाथ यादव ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रश्नपत्र लीक, नकल तथा परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। श्री यादव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा अपराध न केवल मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करते हैं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं। संशोधन विधेयक के माध्यम से ऐसे अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, जिससे परीक्षा माफिया और अनियमितताओं में शामिल तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार युवाओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस निर्णय ले रही है। श्री यादव ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर निष्पक्ष अवसर मिले। यह संशोधन विधेयक ईमानदार प्रतिभाओं को संरक्षण देने तथा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

प्रतापपुर के प्रतिबंधित मार्ग पर बेखौफ फर्राटे भर रही कोयला व बॉक्साइट लोड वाहनें

जर्जर हो रही सड़के, बढ़ा हादसों का खतरा, पुलिस पर लग रहे गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रतापपुर के मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंधित के बावजूद कोयला और बॉक्साइट लोड भारी वाहन बेखौफ होकर गुजर रही हैं।उक्त वाहनें दिनदहाड़े प्रतापपुर थाना के सामने से होकर नगर के व्यस्ततम मार्ग पर फर्राटे भर रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के आदेश और भारी वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस पर भी गम्भीर आरोप लग रहे है। बताया जा रहा है कि आम जनता की सुरक्षा और नगर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा नगर के मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। इस मामले को लेकर पूर्व में भी स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों द्वारा प्रशासन के समक्ष शिकायतें एवं मांगें रखी जाती रही हैं। प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की पहल पर भी इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर पहल की गई है। बावजूद इसके प्रतापपुर मुख्य बाजार से कोयला और बॉक्साइट लोड ट्रक प्रतिबंधित मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं। इसी मार्ग पर स्कूली बच्चों, राहगीरों, व्यापारियों और आम नागरिकों की लगातार आवाजाही रहती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की इस तरह आवाजाही से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। पहले से ही व्यस्त मार्ग पर भारी वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। बताया गया है कि निर्धारित मार्ग को छोड़कर कम दूरी तय करने के उद्देश्य से नगर के इस मार्ग का इस्तेमाल वाहन चालक कर रहे हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही का असर अब सड़क पर भी दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर सड़क उखड़ने लगी है और गड्ढे बनने शुरू हो गए हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि इसी तरह भारी वाहन चलते रहे तो सड़क जल्द ही जर्जर हो सकती है और इसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। लोगो का कहना है कि प्रभावी कार्रवाई के आभाव में ट्रक चालकों के हौसले बुलन्द हैं। भारी वाहनों की तेज आवाजाही के बीच किसी बड़े हादसे की आशंका से लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन को पहले ही सख्ती बरतते हुए नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानीय विधायक शकुंतला सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन से समय रहते कार्रवाई को कहा है। इस मामले में सूरजपुर कलेक्टर द्वारा भी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनो पर नियमानुसार जुमार्ना एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। नागरिकों ने प्रशासन, पुलिस, परिवहन एवं संबंधित विभाग से कार्रवाई कर प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कराए जाने की मांग की है।

की जाएगी कार्रवाई

मामले में एसडीओपी अनूप एक्का ने कहा कि इस तरह के वाहनों की घर पकड़ कर जुमार्ना के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी।

गोविन्दपुर उप.स्वा.केंद्र में जल संकट, फटी टंकी और खराब सोलर पंप बढ़ा रहे मरीजो मुश्किलें

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं देने के बड़े-बड़े सरकारी दावों के बीच प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोविंदपुर से आई तस्वीरें जमीनी हकीकत साफ बयां कर रही हैं। यहाँ के उपस्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगा सौर ऊर्जा चालित जल आपूर्ति प्रणाली पिछले लगभग एक वर्ष से पूरी तरह बंद पड़ा है। देखरेख और रखरखाव के अभाव में इस सिस्टम की विशाल प्लास्टिक की टंकी बीच से पूरी तरह फट चुकी है और इसका स्टार्टर भी महीनों से खराब है। तकनीकी खराबी और विभागीय उदासीनता के कारण उपस्वास्थ्य केंद्र समेत आसपास पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर एक गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है। इस व्यवस्था के ठप होने का सबसे दर्दनाक और गंभीर असर उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज तथा प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं और मरीजों पर पड़ रहा है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर पानी की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों, उनके नवजात शिशुओं और उनके साथ आने वाले परिजनों को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संकट सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा सार्वजनिक नल भी पूरी तरह सूखा पड़ा है। इस वजह से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गोविंदपुर में अपनी फसलों और अन्य कार्यों के लिए आने वाले सैकड़ों किसानों को तपती धूप में पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए यहाँ-वहाँ भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही, स्थानीय मोहल्ले के निवासियों और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के सामने भी पेयजल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पिछले एक साल के भीतर कई बार संबंधित विभाग, जनपद पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों को इस फटी हुई टंकी तथा खराब पड़े स्टार्टर की सुध लेने के लिए लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया है। इसके बावजूद, अब तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है और न ही इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। लगातार हो रही इस अनदेखी और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने अब प्रशासन को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द नई टंकी स्थापित कर और स्टार्टर की मरम्मत करवाकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज

हिंदूवादी नेता अशोक पांडे ने योगी सरकार की कार्रवाई का किया समर्थन

संवाददाता

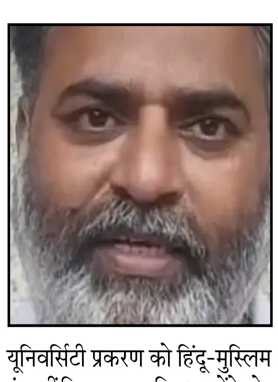

अलीगढ़ , हिंदूवादी नेता अशोक कुमार पांडे ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में अवैध संपत्तियां सामने आती हैं, तो उन पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पांडे ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के योगी सरकार के संदेश को महत्वपूर्ण बताया।

अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की मांग

मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार पांडे ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण को हिंदू-मुस्लिम रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने नियमों के विपरीत संपत्ति अर्जित की है, तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अवैध संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने और अवैध निमार्णों के खिलाफ अभियान चलाने की नीति का उल्लेख किया।

कानून सबके लिए समान

पांडे ने आगे कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी यदि जांच एजेंसियों और प्रशासनिक स्तर पर अवैध संपत्ति या अनियमितताएं साबित होती हैं, तो सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक पहचान या सामाजिक हैसियत के आधार पर छुट नहीं मिलनी चाहिए।

जौहर यूनिवर्सिटी विवाद को सांप्रदायिक रंग न दें

उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, जिन लोगों की जमीन या संपत्तियों को लेकर विवाद सामने आए हैं, उनमें मुस्लिम पक्ष भी शामिल है। इसलिए इसे हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस बनाने के बजाय कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

निष्पक्ष जांच और प्रभावी कदम जरूरी

अशोक कुमार पांडे ने दावा किया कि प्रदेश सरकार की कार्रवाई से अवैध कब्जों और नियम विरुद्ध अर्जित संपत्तियों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत कार्रवाई ही लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की मजबूती का आधार है और जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण में प्रशासन को निष्पक्ष तथा प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

हिंदू संगठन और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

कांवड़ मार्ग की बदहाल सड़कों को लेकर हिंदू युवा संगठन का पैदल मार्च

आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

संवाददाता

शाहजहांपुर ,पुवायां में कांवड़ यात्रा मार्ग की जर्जर सड़कों की मरम्मत और सड़कों पर घूम रहे गौवंश को हटाने की मांग। बुधवार को हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला। जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया। हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्र के नेतृत्व में पुवायां में एकत्र हुए। अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया। संगठन का कहना था कि शाहजहांपुर से नियामतपुर मोड़ और बड़ागांव से पुवायां तक की सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। सावन के दौरान इन्हीं मार्गों से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने तत्काल गड्ढे भरवाकर सड़क दुरुस्त कराने की मांग की। पदाधिकारियों ने सड़कों पर खुले घूम रहे गौवंश को भी कांवड़ यात्रियों के लिए खतरा बताया। उनका कहना था कि रात के समय सड़क पर बैठे या घूम रहे गौवंश आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। संगठन ने प्रशासन से सभी गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग की। उनका कहना था कि इस संबंध में पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई मांगों को लेकर संगठन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय की ओर पैदल मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुवायां पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याएं पुलिस अधिकारियों के सामने रखीं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और संगठन के पदाधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस अधिकारियों ने संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हो गए और मामला समाप्त हो गया।

संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर युवक की मौत

कमरा बंद होने पर परिजनों को हुआ शक; जांच में जुटी पुलिस

संवाददाता

प्रतापगढ़ ,महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर कोट गांव में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम छा गया। झींगुर कोट निवासी सुरेंद्र कुमार द्विवेदी के पुत्र रौनक द्विवेदी (20) शाम करीब 7 बजे अपने घर के अंदर फंदे से लटके मिले। परिजनों को तब संदेह हुआ जब रौनक के कमरे का दरवाजा काफी देर तक बंद रहा। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। परिजनों ने तत्काल रौनक को फंदे से उतारा और एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी कुंडा ले गए। हालांकि, वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर महेशगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने श्रृंग्वेरपुर गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया।बताया गया कि रौनक की मां का निधन लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका था। वह दो भाइयों में छोटे थे, जबकि उनके बड़े भाई विकास दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। इस घटना से पिता सुरेंद्र कुमार द्विवेदी और अन्य परिजनों का दुखद स्थिति है। महेशगंज थाना प्रभारी संदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत मिलती है, तो जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

धान रोपाई कर रही युवती पर लाठी-डंडों से हमला

महिलाओं और युवकों ने पीटा, पुलिस ने मेडिकल कराया

संवाददाता

प्रतापगढ़ , पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कुंदनपुर गांव में धान की रोपाई कर रही एक युवती पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का यह वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया, हालांकि यह घटना सोमवार की बताई जा रही है। कुंदनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सपना सरोज पुत्री कमलेश सरोज शाम करीब 5:30 बजे अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस की कुछ महिलाएं लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचीं और उनके साथ मारपीट करने लगीं। कुछ देर बाद दो युवक भी वहां पहुंचे और युवती की पिटाई की। युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गयायुवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायल सपना सरोज को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पट्टी थाना प्रभारी आनंद पाल सिंह ने ने बताया कि घायल युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। उसे रोहित से बात करने में दिक्कत होती थी। जब भी बात करो, तो बेटा रोने लगता था। 28 जून को भी मैं रोहित से बात कर रही थी। बेटा डिस्टर्ब कर रहा था। गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबा दिया। इसके बाद पति को फोन किया। पत्नी ने जब बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली, तो कृष्ण मुरारी सोमवार को बलदेव थाने पहुंचे। वहां उन्होंने पत्नी रुचि और उसके प्रेमी रोहित के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजय शर्मा ने बताया- पति की शिकायत पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए बच्चे की लाश कब्र से निकालकर उसका पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। महावन के सीओ संजीव राय ने बताया- 27 जुलाई को डायल- 112 पर कृष्ण मुरारी के बड़े भाई गोविंद की ओर से सूचना मिली थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अदालत में पेश करने लाए गए दो आरोपी भागे, एक धराया

दूसरा हुआ छूमंतर, तलाश में जुटी पुलिस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। गुरुवार को यहां अदालत परिसर के बाहर से चोरी के एक आरोपी के भाग खड़े होने की खबरें है।जिसके तलाश में पुलिस जी जान से जुटी हुई है। अब तक फरार आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है।

बताया गया है कि झिलमिली थाने से चोरी के दो आरोपियों को यहां अदालत में पेश करने के लिए लाया गया था।लेकिन जैसे ही अदालत परिसर के समीप पुलिस कर्मी आरोपियों को लेकर पहुँचे वैसे ही दोनो आरोपी भाग निकले। जिसमे एक आरोपी को तो पुलिस धर दबोचने में सफल रही लेकिन दूसरा आरोपी छूमंतर हो गया है। इस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जी जान एक किये हुए है मगर अब तक आरोपी पकड़ा नही गया है।इस सबन्ध में कोतवाली पुलिस ने कोई जानकारी नही होने की बात कही है।

सूत्रों के अनुसार बाइक व मोबाइल चोरी के आरोप में दोनो आरोपियों को पेश करने के लिए लाया गया था ऐसा बताया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि जिस पुलिस कर्मी के गिरफ्त से आरोपी भागा है उस पुलिसकर्मी को आज जारी तबादला सूची में जिले की एक चौकी का प्रभारी बनाया गया है। झिलमिली पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिये जाने की बात कही है।

महिला एवं बाल विकास की समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, की समीक्षा बैठक जिपं अध्यक्ष श्रीमती चंन्द्रमणि पैकरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले, जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति, पोषण अभियान, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, आंगनबाड़ी सेवाएं तथा अन्य विभागीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पैकरा ने जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रो के गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग करने, पोषण संबंधी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ शासन की योजनाओं का पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में सभी परियोजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति, हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ प्रदान करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, पोषण ट्रैकर एप में नियमित एवं त्रुटिरहित प्रविष्टि तथा योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर नियमित भ्रमण कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। विभागीय अधिकारियों एवं परियोजना स्तर के अधिकारियों से योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निराकरण हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश प्रदान किया गया। बैठक में समन्वित प्रयासों के साथ विभागीय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा गया।समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाए। पोषण ट्रैकर एप में नियमित एवं त्रुटिरहित डेटा प्रविष्टि, आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत निरीक्षण, कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा शासन के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक नियमित क्षेत्र भ्रमण कर आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करें, आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि या लंबित प्रकरण का त्वरित निराकरण करें। सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने तथा सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा, समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा शासन द्वारा निर्धारित संकेतकों के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसकी रोकथाम में विभिन्न विभागों एवं समुदाय की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा इसे रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।विशेषज्ञों द्वारा बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई, विभागों के मध्य समन्वय तथा समुदाय स्तर पर जन-जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प भी लिया।महिला एवं बाल विकास विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित प्रशासन, पुलिस अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

थाना परिसर के वायरलेस टावर पर चढ़ी युवती, चार घंटे तक चला हंगामा

एसपी कार्यालय में शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंची थी थाने, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के चांदनी बिहारपुर थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब धोखेबाज प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई एक युवती थाना परिसर में लगे वायरलेस टावर पर चढ़ गई। युवती करीब चार घंटे तक टावर पर डटी रही और अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करती रही। पुलिस, परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार समझाइश दिए जाने के बाद भी वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई। अंततः पुलिस ने काफी मशक्कत और सावधानी बरतते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के दौरान थाना परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना रहा।

जानकारी के अनुसार चांदनी बिहारपुर की आरती कोल अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत लेकर पहले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सूरजपुर पहुंची थी। युवती का कहना था कि उसका प्रेमी उससे संपर्क नहीं कर रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शिकायत को जांच के लिए चांदनी थाना भेजा गया, जिसके बाद युवती अपने पिता के साथ थाने पहुंची। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेम संबंध बृजेश साहू नामक युवक से था, जो पहले मध्यप्रदेश के बैढ़न क्षेत्र में रहकर काम करता था। दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था। बाद में युवक काम के सिलसिले में अन्य स्थान पर चला गया। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत होती रही, लेकिन कुछ समय से युवक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। लगातार संपर्क नहीं होने से युवती मानसिक रूप से परेशान थी और इसी कारण उसने पुलिस से शिकायत की थी। थाने में शिकायत की जांच और पूछताछ की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान युवती अचानक थाना परिसर में लगे वायरलेस टावर पर चढ़ गई। टावर पर चढ़ने के बाद उसने अपने प्रेमी को तत्काल बुलाने की मांग शुरू कर दी। युवती काफी ऊंचाई तक पहुंच गई, जिससे पुलिस और मौजूद लोगों की चिंता बढ़ गई। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था की और युवती को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। करीब चार घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिसकर्मी लगातार युवती को समझाते रहे। उसके परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने भी उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। आखिरकार काफी समझाइश और संयम के बाद पुलिस टीम ने युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद उसकी काउंसिलिंग की गई तथा शिकायत के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाकर परिजनों के साथ घर भेज दिया गया।

मामले की जांच पश्चात की जाएगी कार्रवाई

चांदनी थाना प्रभारी राम प्रताप साहू ने बताया कि युवती द्वारा एक युवक के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के लिए उसे थाने बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान वह अचानक थाना परिसर के वायरलेस टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने धैर्यपूर्वक समझाइश देकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर का असर : महुली स्कूल पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, बच्चों की जांच कर वितरित की दवाइयां

खुजली की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय, स्कूल में लगाया गया शिविर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी-बिहारपुर (सूरजपुर)। महुली स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों और शिक्षकों में लगातार सामने आ रही खुजली एवं त्वचा संबंधी समस्या की खबर को छत्तीसगढ़ फ्रन्टलाइन समाचार पत्र के 31 जुलाई के अंक प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर की चिकित्सा टीम विद्यालय पहुंची और विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर के दौरान टीम ने खुजली और त्वचा संबंधी शिकायत वाले बच्चों की जांच कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया। साथ ही बच्चों और शिक्षकों को साफ-सफाई रखने, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने और किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य टीम ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया और स्कूल प्रबंधन को नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के साथ आवश्यकतानुसार दवा के छिड़काव एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से महुली माध्यमिक शाला में कई बच्चों और कुछ शिक्षकों को अचानक खुजली तथा लाल चकत्तों की शिकायत हो रही थी। इस कारण कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल आना भी बंद कर दिया था। मामले को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।

खबर प्रकाशित होने के तत्काल बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर की टीम के मौके पर पहुंचने से अभिभावकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करता रहे तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

महुली स्कूल में रहस्यमयी खुजली का कहर, 1 सप्ताह से परेशान बच्चे और शिक्षक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी-बिहारपुर। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुली स्थित शासकीय माध्यमिक शाला इन दिनों एक रहस्यमयी खुजली की समस्या से जूझ रही है। पिछले एक सप्ताह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के शरीर पर अचानक तेज खुजली, लाल चकत्ते और एलर्जी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही इस समस्या से स्कूल में भय का माहौल है। स्थिति यह है कि कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल पहुंचने के कुछ समय बाद ही कई बच्चों के हाथ, पैर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में तेज खुजली शुरू हो जाती है। देखते ही देखते लाल धब्बे और चकत्ते उभर आते हैं। कुछ बच्चों को इतनी अधिक परेशानी होती है कि उन्हें बीच में ही घर लौटना पड़ता है। यही समस्या कुछ शिक्षकों के साथ भी देखने को मिली है।

विद्यालय के प्रधान पाठक अखिलेश पटेल ने बताया कि स्कूल में नियमित रूप से

स्कूल आना छोड़े कई बच्चे

साफ-सफाई कराई जा रही है। फिनाइल और अन्य कीटाणुनाशक दवाओं से कक्षाओं की धुलाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिदिन दो से चार बच्चों में खुजली की शिकायत सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन स्वयं भी इस समस्या को लेकर चिंतित है। विद्यालय परिसर में संचालित प्राथमिक शाला के बच्चों में भी कभी-कभी इसी तरह के लक्षण देखने को मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि समस्या पूरे परिसर में फैली हुई हो सकती है।

ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल परिसर के आसपास महुआ और आम के कई पुराने पेड़ हैं। बरसात के मौसम में इन पेड़ों से रोएंदार या जहरीले कीड़े नीचे गिरते हैं। बच्चों के संपर्क में आने पर उनके शरीर में एलर्जी और खुजली की समस्या हो सकती है। हालांकि यह केवल स्थानीय लोगों की आशंका है और इसकी पुष्टि विशेषज्ञ जांच के बाद ही हो सकेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगभग एक सप्ताह पहले दे दी गई थी, लेकिन अब तक न तो स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम स्कूल पहुंची है और न ही पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया है। स्कूल में दवा का छिड़काव भी नहीं कराया गया है। इससे अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इधर अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते स्वास्थ्य विभाग ने पहल नहीं की तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल परिसर में तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाकर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की जांच कराई जाए। साथ ही परिसर में प्रभावी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर संभावित कीटों या एलर्जी के स्रोत की पहचान की जाए।

ग्रामीणों ने कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। समय रहते उचित कदम उठाए जाने से बड़ी समस्या टाली जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खुजली का कारण किसी जहरीले कीड़े का संपर्क है, एलर्जी है या कोई अन्य चिकित्सीय कारण। फिलहाल पूरे गांव की निगाहें स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

मसगा में हाथियों के दल ने रौंदा 4 एकड़ खेत मे लगी धान की फसल, मुआवजे को लेकर छलका किसानों का दर्द

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम मसगा में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार देर रात 12 से 14 ने खेत में घुसकर किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने खेतों में उत्पात मचाते हुए करीब 3 से 4 एकड़ में लगी धान की फसल को रौंद डाला जिससे खेत पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गए और किसानों की मेहनत पलभर में बर्बाद हो गई। पीड़ित किसान अशोक कुमार जायसवाल, संदीप कुमार तथा विकास कुमार ने बताया कि खेती के लिए बैंक से ऋण लेने के साथ-साथ खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री पर बड़ी राशि खर्च की गई थी। अब फसल नष्ट होने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि जब पूरी फसल ही बर्बाद हो गई तो बैंक का कर्ज चुकाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का निरीक्षण किया। किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों ने नुकसान देखने के बाद भी स्पष्ट कहा कि शासन के निर्धारित नियमों के कारण वे चाहकर भी पर्याप्त मुआवजा नहीं दिला सकते। इससे किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वर्तमान मुआवजा व्यवस्था वास्तविक नुकसान की भरपाई करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों का आतंक बना हुआ है, लेकिन वन विभाग की ओर से स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की जा रही। हाथियों के लगातार गांवों और खेतों में पहुंचने से किसानों के साथ-साथ ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। रात होते ही लोग खेतों और घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। फसल नुकसान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन राहत राशि इतनी कम मिलती है कि उससे वास्तविक नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती। ऐसे में किसान आर्थिक रूप से टूटते जा रहे हैं। उन्होंने शासन से मांग की है कि फसल क्षति का वास्तविक आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए तथा हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी और स्थायी उपाय किए जाए।

ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे आगामी कृषि कार्य कर सकें और बैंक ऋण चुकाने में कुछ राहत मिल सके। ग्रामवासियों ने शासन ने मांग करते हुए कहा कि केवल औपचारिक निरीक्षण से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब जरूरत है कि किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका बचाने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए।

अनाधिकृत अनुपस्थिति पर सेवा से पृथक किया गया आरक्षक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने जिला पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 129 दिनों तक बगैर अनुमति एवं सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक अमरदीप विश्वकर्मा को विभागीय जांच के बाद सेवा से पृथक कर दिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने विभागीय जांच, अभियोजन साक्ष्यों, सेवा अभिलेखों तथा उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यह आदेश जारी किया। बताया गया है कि आरक्षक अमरदीप की ड्यूटी 25 जून 2025 को बंदी पेशी के लिए लगाई गई थी, लेकिन वह उस दिन से बिना किसी सक्षम अनुमति अथवा विभाग को सूचना दिए लगातार अनुपस्थित रहा। वह 25 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 129 दिनों तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ। इस दौरान विभाग द्वारा उसे कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण एवं ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। मामले में विभागीय जांच प्रारंभ की गई, जिसमें आरोप पत्र जारी कर आरक्षक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों, अभियोजन साक्ष्यों तथा गवाहों के कथनों

पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश

का परीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आया कि आरक्षक ने उपचार संबंधी दस्तावेज तो प्रस्तुत किए, लेकिन लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के दौरान विभाग को नियमानुसार कोई लिखित सूचना अथवा अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहना तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना गंभीर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित आरक्षक का पूर्व सेवा रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं रहा है। विभाग में नियुक्ति के बाद से वह पूर्व में भी कई बार अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में विभागीय कार्रवाई का सामना

कर चुका है। सेवा अभिलेखों के अनुसार उसे पूर्व में अनेकों छोटी एवं बड़ी विभागीय सजाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके आचरण एवं कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं आया।

आरक्षक के सेवा रिकार्ड से स्पष्ट है कि वह विभाग की सेवा के प्रति गंभीर नहीं है। आरक्षक के भविष्य में एक सफल एवं अनुशासित पुलिस कर्मचारी बने रहने की संभावना नहीं के बराबर है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने संबंधित आरक्षक को 31 जुलाई 2026 को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया। साथ ही 25 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक की 129 दिनों की अनुपस्थिति अवधि को छत्तीसगढ़ पुलिस नियमों के अनुसार कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत के तहत अवैतनिक घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है, जहां प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से कर्तव्यनिष्ठा, जवाबदेही और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। विभागीय नियमों का उल्लंघन, अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस में अनुशासनहीनता के मामलों में भविष्य में भी निष्पक्ष एवं नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पुलिस बल की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनविश्वास कायम रहे।

जल संचय कार्यों से खेतों तक पहुंचा संबल, रोजगार के साथ सिंचाई की सुविधा भी हुई सुलभ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में शासन की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी-राम-जी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर तालाब गहरीकरण, मिट्टी बांध, आजीविका डबरी निर्माण सहित विभिन्न कार्य कराए गए। मानसून की अच्छी बारिश के बाद इन जल संरचनाओं में पानी लबालब भर गया है, जिससे जिले के भैयाथान विकासखंड के किसानों और ग्रामीणों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। योजना ने रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण के अपने उद्देश्य को भी सफलतापूर्वक साकार किया है।

पहले वर्षा जल के संरक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने से बारिश का अधिकांश पानी बह जाता था। किसानों को धान की रोपाई के समय सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता था, जिससे रोपाई में देरी होती थी। लेकिन अब विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत निर्मित आजीविका डबरियों, तालाबों एवं अन्य जल संरचनाओं में वर्षा जल सुरक्षित संचित हो रहा है। यही पानी किसानों के लिए धान की रोपाई का प्रमुख सहारा बन रहा है। पहले जहां पानी की अनुपलब्धता चुनौती थी, वहीं अब जल स्रोतों के लबालब भर जाने से समय पर कृषि कार्य पूरे हो रहे हैं। यह बदलाव क्षेत्र में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। क्षेत्र के किसान बताते हैं कि योजना के तहत हुए कार्यों से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला और आज उन्हीं जल संरचनाओं का लाभ उनकी खेती को मिल रहा है। आजीविका डबरियों में संचित जल का उपयोग धान की रोपाई सहित अन्य कृषि कार्यों में किया जा रहा है।

इससे खेती आसान हुई है, श्रम और समय की बचत हो रही है तथा बेहतर उत्पादन की उम्मीद भी बढ़ी है।

सहायक शिक्षक भर्ती में पीवीटीजी समाज के अभ्यर्थियों के लिए पूर्ववत प्रावधान लागू करें

सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो के नेतृत्व में पीवीटीजी समाज के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती में पूर्ववत समाज के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान लागू करने की मांग की गई है।

समिति ने कहा है कि शासन द्वारा वर्ष 2026 में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन इस भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में लागू विशेष प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे इस वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं।

बताया गया है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग में पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया एवं पण्डो समाज शामिल हैं। यह वर्ग आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ा है। शासन द्वारा पूर्व में इस वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जिस कारण बड़ी संख्या में इस वर्ग से अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। समाज ने बताया है कि पूर्व की भर्ती में एसटी के कुल पदों में से 20 प्रतिशत पद पीवीटीजी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे और ऑनलाइन फार्म में इनके लिए अलग विकल्प भी दिया गया था, लेकिन 2026 की भर्ती में ये दोनों प्रावधान हटा दिए जाने से इस वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश सचिव पण्डो जनजाति समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो के साथ, संभागीय उपाध्यक्ष राजकुमार पण्डो, रामकुमार पण्डो, केशरी पण्डो, रंजीत, रजनी पहाड़ी कोरवा सहित पीवीटीजी वर्ग के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएं

सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति की ओर से मांग की गई है कि सहायक शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन फार्म में पीवीटीजी अभ्यर्थियों के लिए पूर्व की भांति अलग विकल्प पुनः जोड़ा जाए। कुल पदों में से 20 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए जाएं। अभ्यर्थियों को टेट, डी.एड, बी.एड की योग्यता में छूट प्रदान करके नियुक्ति दिनांक से 5 वर्ष के अंदर योग्यता पूर्ण करने की सुविधा दी जाए। लगभग 3 वर्ष पूर्व भर्ती किए गए 400-500 पीवीटीजी सहायक शिक्षकों के लिए शासन स्तर पर विभागीय डी.एल.एड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो पीवीटीजी अभ्यर्थी डी.एल.एड कर लिए हैं, लेकिन कक्षा 12वीं में 45 प्रतिशत अंक नहीं होने से अप्रशिक्षित माने जा रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित श्रेणी में मान्यता प्रदान की जाए।

नाबालिकों के वाहन चलाने पर पुलिस सख्त, 26 मामलों में कार्रवाई

25 हजार रुपये जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक जिलेभर में 26 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है।

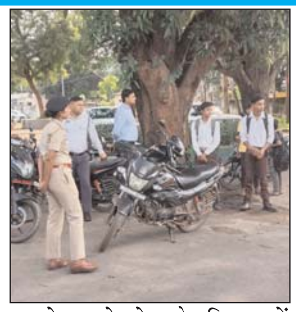

अभियान के दौरान जिले के सभी थाना एवं चौकी पुलिस को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के आसपास विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत विद्यालयों की छुट्टी के समय पुलिस टीमों ने स्कूल परिसरों और मुख्य मार्गों पर जांच कर नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों को रोककर कार्रवाई की। जिन विद्यार्थियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया अथवा जो नाबालिग होकर वाहन चलाते मिले उनके वाहनों को विधिवत जप्त कर संबंधित थाना एवं चौकी लाया गया। पुलिस ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें ऑटो, बस अथवा अन्य सुरक्षित माध्यमों से घर भेजने की व्यवस्था भी की। इसके साथ ही संबंधित अभिभावकों को थाना बुलाकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत चालानी कार्रवाई की। जिले भर में 26 प्रकरण में 39000 रुपये वसूला गया, और नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने की सख्त हिदायत दी गई।

जागरूकता अभियान भी चला रही पुलिस

यातायात पुलिस ने अभियान को केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा नाबालिक छात्र-छात्राओं को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई छात्र-छात्रा नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जुर्माना और कारावास का है प्रावधान

विशेष अभियान लगातार एक सप्ताह तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान चालानी कार्रवाई के साथ-साथ अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। यदि इसके बाद भी नियमों की अनदेखी जारी रही तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाहन उपलब्ध कराने वाले पालक अथवा अभिभावक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक का कारावास तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। जिला पुलिस द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को कानून की जानकारी दी जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

जुलाई माह में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई

नाबालिक वाहन चालकों के विरुद्ध माह जुलाई में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। थाना बलरामपुर ने 02 प्रकरण में 4000, बारियों ने 02 प्रकरण में 2000, पास्ता ने 01 प्रकरण में 2000, डवरा ने 03 प्रकरण में 6000, रामानुजगंज ने 6 प्रकरण में 6000, तातापानी ने 01 प्रकरण में 2000, सनावल ने 05 प्रकरण में 5000, वाड्रफनगर ने 01 प्रकरण में 2000, यातायात पुलिस ने 05 प्रकरण में 10000 रुपये की चालानी कार्रवाई की है।

> नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वैध ड्राइविंग लाइसेंस बिना वाहन चलाने की अनुमति नहीं दें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करने प्रेरित करें, इसके लिए अभिभावकों से अपील की जा रही है। जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अभियान पूरे प्रदेश सहित हमारे जिले में बच्चों के सुरक्षित भविष्य और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है।
>
> **वैभव बैंकर**
> **पुलिस अधीक्षक बलरामपुर**

प्रेम विवाह की वृद्ध महिला से मौत के बाद भी अपनों ने बनाई दूरी

महापौर ने अंतिम संस्कार कराया, पेश की मानवता की मिशाल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। प्रेम विवाह करने की वजह से एक महिला का उसके परिवार और समाज ने न सिर्फ जीते जी बहिष्कार किया, बल्कि मौत के बाद भी अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। आखिरकार अंबिकापुर नगर पालिक निगम की महापौर मंजूषा भगत ने आगे आकर ससम्मान अंतिम संस्कार कराकर मानवता की मिशाल पेश की। मामला शहर के वार्ड क्रमांक 4 शंकरनगर का है। 75 वर्षीय सावित्री बाई के पति की मौत सालों पहले हो गई थी। पति के निधन के बाद उन्होंने घर-परिवार के विरोध के बावजूद दूसरे समाज के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लिया था। बस यहीं से उनका बहिष्कार शुरू हो गया। परिवार के

लोगों ने ही नहीं, पूरे समाज ने उनसे नाता तोड़ लिया। सालों बीत गए लेकिन बहिष्कार खत्म नहीं हुआ। 75 वर्ष की उम्र में जब सावित्री बाई का निधन हुआ तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। न परिवार आया, न समाज के लोग।

जब यह बात महापौर मंजूषा भगत को पता चली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचीं। महापौर ने नगर निगम की जेसीबी से गड्ढा खुदवाया और सामाजिक परंपराओं के अनुसार महिला का अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान महापौर खुद वहां मौजूद रहीं। जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति से सावित्री बाई ने प्रेम विवाह किया था वह उनका अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन उसके घरवालों ने मना कर दिया। महिला की कोई संतान नहीं थी।

इस घटना पर महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि 'जब समाज अपने ही लोगों के अंतिम समय में साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो ऐसे समाज का क्या फायदा। इंसानियत सबसे बड़ी है।' उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि जाति और समाज के लोग अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। महापौर के इस कदम की पूरे शहर में सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रेम के नाम पर किया गया बहिष्कार मौत के बाद भी जारी रखना समाज के लिए कलंक है।

स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था का मंत्री द्वारा निरीक्षण सवालों के घेरे में

छ.ग.फ्रंटलाइन भटगांव। महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंत्री को क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी वास्तविक स्थिति दिखाई गई या केवल सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की गई। सवाल उठ रहा है कि पहले प्रसूता के जमीन पर प्रसव जैसे चर्चित मामले में जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी, वे दोबारा उसी अस्पताल में कैसे पदस्थ हो गए और उस कार्रवाई का अंतिम परिणाम क्या रहा।

वहीं न्यू माइंस भटगांव स्थित हमर क्लिनिक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद क्लिनिक की उपयोगिता, मरीजों की संख्या, दवा वितरण, स्टाफ की नियमित उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा नहीं हुई। लोगों का यह भी दावा है कि पिछले कुछ वर्षों से वहां नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा और मंत्री के दौरे में भी हमर क्लिनिक समीक्षा से बाहर रहा। आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी जनसमस्याओं की बजाय केवल औपचारिक स्वागत और फोटो तक सीमित रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य समेत अन्य मूलभूत समस्याएं प्रभावी ढंग से सामने नहीं आ पातीं। लोगों का कहना है कि सुशासन की पहचान केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी सुधार से होती है।

ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती, 2 बाइक चालकों पर 20 हजार का जुर्माना

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में यातायात शाखा ने शराब पीकर वाहन चलाने के 2 मामलों में मोटरसायकल चालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।

जानकारी के मुताबिक, यातायात शाखा की टीम चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी 29 एजी 3955 के सवार राजू राजवाड़े पिता बिशुन राजवाड़े 24 वर्ष, निवासी ग्राम बतरा, थाना जयनगर को रोकी तो वह नशे में धुत्त मिला। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर नशे की पुष्टि हुई। दूसरे प्रकरण में टीम ने मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 ईडी 3861 के चालक राकेश तिर्की पिता राजकुमार तिर्की 29 वर्ष, निवासी पटपरिया, थाना गांधीनगर को रोका। वह भी शराब पीकर बाइक चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर में वह भी पॉजिटिव पाया गया। दोनों चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन्हें अलग-अलग 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ चालक के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी जानलेवा है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं।

नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं

भाजपा ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, दबाव बनाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा के ग्राम भफौली में नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाए जाने से भाजपा में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी तरुण जायसवाल की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की,पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फुलेश्वरी सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अरुणा सिंह, निलेश सिंह, सत्यम साहू, जन्मेजय मिश्रा, रूपेश दुबे, रविकांत उरांव, प्रियंका चौबे, सरस्वती यादव, अनीश सिंह, अविनाश मण्डल* सहित मोर्चा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आरोपी प्रभावशाली, साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी पैकरा ने कहा कि नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ हुई घटना से पूरा समाज आक्रोशित है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी तरुण जायसवाल और उसके परिवारजन काफी प्रभावशाली हैं और अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर प्रकरण को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं हुई तो वह पीड़िता और अन्य साक्षियों को प्रभावित कर सकता है।

अस्मिता से सौदा करना बेहद निंदनीय

बिंदेश्वरी पैकरा ने कांग्रेस नेता पर भी गंभीर आरोप

लगाते हुए कहा कि परसा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच विवेक पैकरा और उनके परिवार के लोग पीड़ित परिवार को आर्थिक प्रलोभन देकर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। 'आदिवासी अस्मिता से सौदा करना बेहद निंदनीय है। इससे कांग्रेस की आदिवासी समाज के प्रति सोच साफ झलकती है।

न्याय में देरी से भरोसा टूटेगा

भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि, आरोपी पक्ष लगातार पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहा है। यदि ऐसे संवेदनशील मामलों में दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा।

महिला मोर्चा पीड़ित परिवार के साथ

भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े ने बताया कि महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ग्राम भफौली जाकर पीड़िता और उसके परिजनों से मिला था। महिला मोर्चा इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभ्य समाज में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध अस्वीकार्य हैं।

परेड सलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहन

डीआईजी एवं एसएसपी ने रक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने 31 जुलाई, शुक्रवार को रक्षित केंद्र अंबिकापुर का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने रक्षित केंद्र में परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर अधिकारी-कर्मचारियों का टर्नआउट चेक किया। जवानों से टोलीवार मार्च पास्ट एवं स्कॉट ड्रिल कराई गई। परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नकद ईनाम देकर पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी एवं एसएसपी ने वाहन शाखा, आर्म्स शाखा, स्टोर शाखा एवं पुलिस यूनिट बैंक का बारीकी से अवलोकन किया। वाहन शाखा में शासकीय वाहनों की अद्यतन स्थिति, रख-रखाव एवं लॉग बुक सहित दस्तावेजों की जांच की। बीपी वाहन एवं जैमर वाहन सहित अन्य वाहनों को सही हालत में रखने के निर्देश रक्षित निरीक्षक एवं वाहन शाखा प्रभारी को दिए। स्टोर शाखा में रखी सामग्रियों के रख-रखाव एवं जवानों को समय पर वितरण करने के निर्देश दिए गए। उपकरणों की समय-समय पर मरम्मत कराने और मेंटनेंस बनाए रखने कहा। आर्म्स शाखा में हथियारों की सुरक्षा, नियमित सफाई एवं मेंटेनेंस के आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी ने पुलिस यूनिट बैंक का निरीक्षण करके जवानों के वेलफेयर के लिए बैंक से अधिकारियों-कर्मचारियों

को अधिक से अधिक लाभान्वित करने कहा।

जवानों की समस्याएं सुनी, दिए निर्देश

डीआईजी एवं एसएसपी ने अधिकारी-कर्मचारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े इस प्रकार संवेदनशील होकर कार्य करें। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय से जिले को आबंटित नए शासकीय वाहन की पूजा-पाठ कर बेहतर रख-रखाव के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमोलक सिंह ढिल्लो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चैधरी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण राकेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक अमृत कुजूर, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, प्रशिक्षु सूबेदार द्वय पेमिन वर्मा व गुलशन चंद्रा, रीडर अमित पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सेवा का बड़ा केंद्र बना रामानुजगंज

छ.ग.फ्रंटलाइन रामानुजगंज। नगर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन इन दिनों आस्था, सेवा और श्रद्धा का संगम बना हुआ है। यहां बाबा बैजनाथ धाम कांवरिया सेवा समिति, रामानुजगंज द्वारा पूरे श्रावण मास के दौरान बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए निशुल्क ठहरने, भोजन, भजन-कीर्तन एवं

अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। समिति की ओर से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। एक साथ 500 से अधिक यात्रियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। सेवा केंद्र की रसोई 24 घंटे संचालित रहती है, जहां श्रद्धालुओं के लिए निरंतर भोजन तैयार किया जाता है। समिति द्वारा यह सेवा कार्य पिछले कई वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज इसकी पहचान केवल रामानुजगंज या बलरामपुर जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। यहां प्रतिदिन तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो वर्षों से इसी सेवा केंद्र में रुकते आ रहे हैं और इसे अपनी यात्रा का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। श्रद्धालुओं में हरदी बाजार के वरिष्ठ अधिवक्ता लखन राठौर भी शामिल हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बाबा बैजनाथ धाम कांवरिया सेवा समिति रामानुजगंज का बैनर लगवाकर इस सेवा कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है। मध्य प्रदेश के बिजुरी में लेट लतीफ कांवरिया संघ द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर समिति के बैनर लगाए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी रामानुजगंज की इस सेवा समिति के बैनर लगाए गए हैं, जो नगर के लिए गर्व का विषय बन गया है। सेवा केंद्र में भजन-कीर्तन, सामूहिक आरती और धार्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भर देता है। यहां आस्था, विश्वास, भाईचारा और सेवा भाव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नगर के विभिन्न वर्गों के लोग तन-मन-धन से इस सेवा कार्य में सहयोग कर रहे हैं।

नगर के सभी वर्गों का मिल रहा सहयोग

नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि, नगर वासियों के सहयोग से संचालित यह सेवा आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे रामानुजगंज नगर के लिए गर्व की बात है कि यहां आने वाले हजारों कांवड़ यात्रियों की निःस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। नगर के सभी वर्गों का सहयोग इस सेवा अभियान की सबसे बड़ी ताकत है।

अंडरएज ड्राइविंग पर सरगुजा पुलिस कस रही शिकंजा

स्कूलों में जागरूकता अभियान तेज, अभिभावकों की होगी काउंसलिंग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़कों पर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरगुजा पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। शासन के निर्देश और डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में यातायात पुलिस और थाना-चैकी की टीमों द्वारा जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नाबालिग छात्र-छात्राओं की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाना है। पुलिस टीम स्कूलों में जाकर छात्र-छात्राओं को एकत्रित कर यातायात नियमों का पालन करने और अंडरएज ड्राइविंग के खतरों के बारे में जानकारी दे रही है। जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधान पाठकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी छात्र-छात्रा को दोपहिया वाहन से स्कूल आने की अनुमति न दें। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो पहले उसे समझाईस दी जाएगी, साथ ही उसके अभिभावकों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलानी कार्रवाई और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम द्वारा अभियान के दौरान मौके पर वाहन चलाते मिले छात्रों से ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के संबंध में पूछताछ भी की गई। उन्हें बताया गया कि बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। छात्र-छात्राओं को स्कूल के अधिकृत वाहन या परिजनों के साथ ही स्कूल आने-जाने की सलाह दी गई। सरगुजा पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने न दें। यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा।

न्यायालय में पदस्थ भृत्य की जहर सेवन से मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर न्यायालय में पदस्थ भृत्य ने अज्ञात कारणों से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक, ओमप्रकाश 53 वर्ष, मूलतः सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिठवा के रहने वाले थे, जो वर्तमान में सूरजपुर जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत अमनदोन में रहकर प्रतापपुर न्यायालय में भृत्य के पद पर सेवारत थे। 27 जुलाई को वे बाजारडांड प्रतापपुर में जहर सेवन कर लिए। प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर संजीवनी 108 एम्बुलेंस से भेजा गया। इसकी जानकारी मिलने पर स्वजन पहुंचे, जहर सेवन का कारण पूछने पर वे कुछ नहीं बताए। इलाज के दौरान 30 जुलाई को रात करीब 8.30 बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर